



यूपी एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची 2.89 करोड़ नाम कटे

12.55 करोड़ मतदाता, 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी

जन एक्सप्रेस। लखनऊ

यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है। अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी विस्तार से जानकारी दे रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ यानी 18 फीसदी नाम कट गए। उन्होंने बताया कि आज यानी 6 जनवरी से दावे-आपत्तियां की जा सकती हैं। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 6 फरवरी तक फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 16 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां मुफ्त हैं। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर- 1950 जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष केंद्र लगाने की योजना बनाई है।



वेबसाइट से सीधे अपना नाम देख सकते हैं: निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन अधिकारी ने कहा, आप वेबसाइट से सीधे अपना नाम देख सकते हैं। 27 अक्टूबर 2025 से प्रक्रिया शुरू हुई। 4 नवंबर से पहला चरण शुरू हुआ। उस वक्त 15 करोड़ 30 हजार 92 मतदाता थे। सभी का गणना प्रपत्र प्रिंट आउट लिया था। प्रपत्र घर-घर जाकर दिए गए। बताया- पहले एक सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया। फिर 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था। 2.97 लाख नाम हट रहे थे, इसके लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। 26 दिसंबर तक गणना चरण चला। उन्होंने कहा- एक मतदाता बूथ पर 1200 से अधिक वोट नहीं रहेंगे, पहले 1500 था। जहां अधिक मतदाता थे, वहां नए बूथ बने। 15030 नए बूथ बने। गणना प्रपत्र जो मिले उनकी संख्या 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 रही। सवाल कीजिएगा कि पहले तो 15.44 करोड़ मतदाता बताए गए थे।

दूसरे चरण में क्या होगा: ड्राफ्ट प्रकाशन और आगे की प्रक्रिया जानिए

एसआईआर का दूसरा चरण मंगलवार से शुरू हो रहा है, जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। पहले ये समय-सारणी में 31 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित होनी थी। लेकिन राजनीतिक दलों की मांग पर इसे 6 जनवरी तक बढ़ाया गया। इस संशोधन के साथ, दावे और आपत्तियों की अवधि भी बढ़ाकर 6 फरवरी, 2026 तक कर दी गई है। इसके बाद दावों और आपत्तियों का निपटारा 26 फरवरी तक होगा। अंतिम मतदाता सूची मार्च के पहले सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी। दूसरे चरण का मुख्य फोकस मतदाताओं को अपनी स्थिति जांचने और सुधार करने का अवसर देना है। ड्राफ्ट सूची में नाम न होने पर नए पंजीकरण, गलतियों पर सुधार या अनुचित नामों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। आयोग ने कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए, इसलिए नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

'नोटिस दिया जाना शुरू किया जा रहा, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी'

उन्होंने बताया- राजनीतिक दलों ने 5766211 बूथ एजेंट तैनात किए गए थे। एक महीने तक दावा और आपत्ति अवधि शुरू हो रही है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक कर सकेंगे। 16 जनवरी से नोटिस भी दिया जाना शुरू किया जा रहा है। जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी।

लखनऊ जिले में 30 प्रतिशत वोट कटे

लखनऊ जिले में 30 प्रतिशत वोट कटे हैं। यहां पहले 39,94,535 थे, जो अब 27,94,397 बचे हैं। इसी तरह बलरामपुर में 25.98 प्रतिशत वोट कटे हैं। यहां पहले 15,83,027 वोट थे, जो अब 11,71,826 बचे हैं। हापुड में 22.30 प्रतिशत वोट कटे हैं। यहां 11,56,699 थे, जो 8,98,796 बचे हैं। इसी तरह से सभल में 20.29 प्रतिशत वोट कटे हैं।

'1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फार्म भर सकते हैं'

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया- 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फार्म भर सकते हैं। 1 अक्टूबर से जो एलिजबल हो रहे हैं, वे फार्म भर सकते हैं।

फॉर्म-6, 6ए, 7, 8 के बारे में जानिए

उन्होंने बताया- एपिक नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। ईसीआई नेट एप पर भी जानकारी देखी जा सकती है। नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दें। फॉर्म-8 करेक्शन के लिए भरा जाएगा। फर्म 7 डिप्टी कराने के लिए भरा जाएगा। 6-ए विदेश में रहने वालों के लिए है। पासपोर्ट के एड्रेस के विधानसभा क्षेत्र में भरे जाएंगे।

कहां कम हो गए वोट

लखनऊ जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थिति अधिक चिंताजनक रही, जहां 39 लाख मतदाताओं में से 12 लाख वोट कम हो गए। इनमें 5.4 लाख देहरी पंजीकरण वाले और 4.3 लाख अनट्रैसेबल थे। शहरी क्षेत्रों में फॉर्म कलेक्शन की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रही, क्योंकि लोग काम या माइग्रेशन के कारण घर पर उपलब्ध नहीं थे। कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में भी यही समस्या देखने को मिली। प्रमुख जिलों में लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 11.56 लाख, कानपुर नगर 9 लाख, आगरा में 8.36 लाख, गाजियाबाद में 8.18 लाख वोट कम हो गए।

पहले चरण में क्या हुआ?

एसआईआर का पहला चरण 4 नवंबर, 2025 से शुरू हुआ। इसमें बीएलओ ने घर-घर जाकर फॉर्म बांटे और मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा की। पहले यह चरण 4 दिसंबर तक चलना था। लेकिन, विपक्ष की मांग पर पहले इसे 7 दिन बढ़ाया गया, फिर 15 दिन का समय बढ़ाया गया। पहले चरण में 2003 की मतदाता सूची से तुलना की गई और मौजूद वोटर की उम्र मैपिंग की गई।

'करीब 9 प्रतिशत लोगों को मैपिंग के लिए नोटिस जाएगा'

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया- जिनका फॉर्म मिला है, उनकी मैपिंग नहीं है। उन्हीं को नोटिस दिया जाएगा। 91 प्रतिशत से अधिक मैपिंग हुई है। करीब 9 प्रतिशत लोगों को मैपिंग के लिए नोटिस जाएगा। 1.4 करोड़ ऐसी संख्या है। 16 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

अंकिता भंडारी केस पर खुलकर बोले धामी, अंकिता के पिता से बात करूंगा, हम हर जांच के लिए हैं तैयार

वायरल ऑडियो-वीडियो की सत्यता की जांच जरूरी, दोषियों को मिल चुकी है आजीवन कारावास की सजा



जन एक्सप्रेस। देहरादून

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो-वीडियो की सत्यता की जांच बेहद जरूरी है और इस मामले में मनमाने आरोप नहीं लगाने चाहिए।

उत्तराखंड में गुस्सा, देश में समर्थन

अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला पिछले दिनों फिर चर्चा में आया जब इसके संबंध में एक ऑडियो-वीडियो वायरल हुआ। ऑडियो में दावा किया गया कि यह बालचौत पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के बीच थी। इसके बाद देशभर में इस प्रकरण पर गुस्सा देखने को मिला। दिल्ली में प्रवासियों ने इंसफ की मांग को लेकर मार्च निकाला और पूरे उत्तराखंड में सीबीआई जांच की मांग उठी।

जांच पूरी हो चुकी, दोषियों को सजा मिली: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकरण पर एसआईटी द्वारा जांच की गई थी और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई जा चुकी है। उन्होंने ऑडियो-वीडियो पर सवाल उठाते हुए कहा कि बातचीत में कभी हत्या और कभी

हमारे प्रभारी जी ने सब वैरिफाई कर दिया है: धामी

सीएम धामी ने आगे कहा, 'हमारे प्रभारी जी (दुष्यंत गौतम) ने पुलिस में सब वैरिफाई कर दिया। उन्होंने सबूत के साथ बात दिया कि वे 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उत्तराखंड में ही नहीं थे। अगर आरोप लगाने वालों के पास कुछ है तो वे भागे क्यों हैं? हम इसी मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है? हमने जांच शुरू कर दी है। वे फोन बंद करके चुप बैठे हैं। मैं सुरेश राठौर से कहता हूँ कि वे आए और सबूत पेश करें।'

ऑडियो-वीडियो की सत्यता की जांच जरूरी

धामी ने आगे कहा कि उस समय भी हाई कोर्ट, सुप्रीमकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग उठी थी, लेकिन अगर न्यायालय को अगर ऐसा लगता कि एसआईटी जांच में कुछ भी रह गया है तो सीबीआई जांच के आदेश तब ही दे दिए जाते। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर हाल ही में ऑडियो-वीडियो वायरल हुए हैं। इनकी सत्यता जरूरी है, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी का भी नाम गंभीरता से नहीं लेता। बिना सत्यता के इन्हें माना नहीं जा सकता। हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसआईटी गठित की और जांच शुरू कर दी है। हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई भी सबूत है तो एसआईटी को सौंपा जाए ताकि मामले की गहरता से जांच हो सके।

कभी हत्या तो कभी आत्महत्या बताते हैं: धामी

धामी ने आगे कहा कि अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो वे सामने आए और भागे नहीं। सबूत दें। हम निश्चित तौर पर जांच करेंगे और दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ ऐश्वर्य लेंगे। आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भ्रम की स्थिति पैदा करके वे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह कैसी सच्चाई है? ऑडियो मैंने भी सुना है... कभी कहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की दूज में था। कभी कहते हैं कि उसकी हत्या हुई तो कभी आत्महत्या बताते हैं... अगर इस तरह का भ्रम न्यायालय में पेश किया जाए तो संभव है कि इससे दोषियों को ही लाभ होगा।

आत्महत्या की बातें हो रही हैं, इसलिए इसकी सत्यता पर ध्यान देना जरूरी है।

मीडिया और जनता को भी अपील

धामी ने पत्रकारवर्ता में कहा कि उस समय भी उन्होंने अखबारों में

करोड़ों की ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी के खिलाफ 113 लोगों ने कराई रिपोर्ट, मामले में 42 आरोपी

जन एक्सप्रेस। बरेली

बरेली में कैनविज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी के खिलाफ ठगी के 35 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के पास ठगी की शिकायतों की भरमार थी। ऐसे में बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने एक संयुक्त रिपोर्ट वादी के तौर पर अपने ही थाने में दर्ज कराई है। इसमें कन्हैया गुलाटी व उसके परिजनों, गुर्गों और एजेंटों को मिलाकर करीब 42 आरोपी हैं। पीड़ित निवेशकों व शिकायतकर्ताओं की संख्या 113 है। बता दें कि कन्हैया गुलाटी और उसकी कंपनी पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। गुलाटी के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित

की गई है। कन्हैया गुलाटी और उसके एक गुर्गों के खिलाफ फरीदपुर कोतवाली में सोमवार को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दोनों पर दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गांव अंधपुरा में कैनविज कॉलोनी में प्लॉट बेचने के नाम पर ठगी का आरोप है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर निवासी गीता गुप्ता ने फरीदपुर थाने में तहरीर में बताया कि उन्होंने कैनविज समूह के मालिक कन्हैया गुलाटी की कंपनी कैनविज इंप्रो कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षर गुलाब नगर निवासी सूर्य प्रकाश से कैनविज विज्ञान वैली प्रोजेक्ट हदयपुर उर्फ अंधपुरा में 159 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा था। प्लॉट पर आज तक उनको मलिकाना हक नहीं दिया गया है।

खटारा 108 एंबुलेंस ने ली मरीज की जान! रास्ते में जवाब दे गई सरकारी एंबुलेंस, तड़पता रहा मरीज, अस्पताल पहुंचते-पहुंचते मौत

जन एक्सप्रेस। चित्रकूट

मानिकपुर। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मानिकपुर क्षेत्र में 108 एंबुलेंस सेवा की खटारा हालत के चलते एक बीमार मरीज की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि अगर एंबुलेंस समय पर और सही हालत में होती, तो आज उनके परिवार का सदस्य जिंदा होता। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान प्रसाद सिंह, निवासी इन्द्रनगर मानिकपुर, गंधौर रूपा से बीमार थे। परिजनों ने तत्काल सरकारी 108 एंबुलेंस को कॉल किया। एंबुलेंस देरी से मौके पर पहुंची,



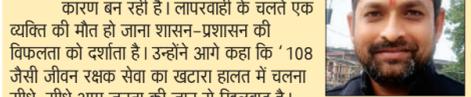
लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकारने वाली घटना इसके बाद हुई। मरीज को लेकर एंबुलेंस जैसे ही अस्पताल की ओर चली, रास्ते में अचानक एंबुलेंस खराब हो गई। एंबुलेंस बीच रास्ते खड़ी हो गई और मरीज अंदर ही तड़पता रहा। काफी देर तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। स्थिति विगड़ती देख परिजनों ने मजबूरी में आनन-फानन में एक

बड़ा सवाल

- जब 108 एंबुलेंस जैसी जीवन रक्षक सेवा खुद ही दम तोड़ दे, तो आम जनता किसके भरोसे रहे?
- क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा?
- यह घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और 108 एंबुलेंस सेवा की हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखा जाये कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।

प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम किया और

'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि जिस एंबुलेंस सेवा का मकसद लोगों की जान बचाना है, वही सेवा आज जान लेने का कारण बन रही है। लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो जाना शासन-प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि '108 जैसी जीवन रक्षक सेवा का खटारा हालत में चलना सीधे-सीधे आम जनता की जान से खिलवाड़ है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।'



-सौरभ मिश्रा, सपा नगर अध्यक्ष

परिजनों का फूटा गुस्सा

मृतक के परिजनों ने 108 एंबुलेंस सेवा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 'अगर एंबुलेंस रास्ते में खराब नहीं होती, अगर सुचारु पर पहुंचती, तो हमारे पिता की जान बच सकती थी। यह सीधी-सीधी लापरवाही है। मृतक पुत्र हेमराज सिंह ने खटारा एंबुलेंसों को सड़कों पर दौड़ाने और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है।

अपने पिता को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर का बयान, एंबुलेंस ड्राइवर ने बताया कि 'गाड़ी अचानक खराब हो गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। इसके बाद परिजन मरीज को प्राइवेट गाड़ी से ले गए।

कैबिनेट फैसले: उत्तर प्रदेश में घटाई गई स्टांप ड्यूटी, सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3,000 करोड़ का निवेश

जन एक्सप्रेस। लखनऊ

यूपी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मंत्रीमंडल की मुहर लगी। इसमें सबसे प्रमुख फैसला स्टांप ड्यूटी को लेकर था। इस फैसले के अनुसार अब व्यावसायिक भूमि का परिवार के सदस्यों के नाम करने पर मात्र 5 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत शुल्क ही लिया जाएगा। अभी तक यह सुविधा कृषि व आवासीय भूमि पर थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्ठादि अचल संपत्ति के दान विलेख पर प्रभाय स्टांप शुल्क में दी जा रही छूट के दावों को और व्यापक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से अब पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दान विलेखों के दान के मूल्य के अनुसार हस्तांतरण पत्र (कनवेंस डीड) की भांति स्टांप शुल्क देय होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्ति के दान विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है।



5,000 तक सीमित है स्टांप शुल्क
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की 3 अगस्त 2023 की अधिसूचना के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि यदि अचल संपत्ति का दान परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया जाता है तो स्टांप शुल्क में छूट देते हुए अधिकतम 5,000 ही लिया जाएगा। यह छूट अब तक केवल कृषि एवं आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। योगी कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इस छूट को पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली हो जाएगी।

सेमीकंडक्टर सेक्टर में 3,000 करोड़ निवेश पर विशेष प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2024 में लाई गई सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

केस-टू-केस आधार पर मिलेगा प्रोत्साहन

सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी क्रम में भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन देने की स्वीकृति दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत डीपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम 2,000 प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट और 10 वर्षों तक प्रति यूनिट 2 रुपये बिजली बिल में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करना है।

उत्तर प्रदेश बनेगा वैश्विक सर्विस का केंद्र, जीसीसी नीति को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक निवेश, उच्च स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में नई गति मिलेगी। कैबिनेट से अनुमोदित नियमावली के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति-2024 के प्रख्यापन की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। जो राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी।

प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नदी ने बताया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसके चलते निवेश करने के लिए उद्योग घराने और मल्टीनेशनल कंपनियों संपर्क में हैं। इसके लिए जीसीसी नीति बहुत लाभप्रद है और आज इसकी एअपली लेबर आए हैं।

फर्जी डिग्री देने पर जेएस विवि की मान्यता रद्द

बैक डेट में बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश देकर फर्जी अंकतालिका व डिग्री जारी करने, अभियुक्तों के साथ संगठित अपराध के रूप में काम करने पर जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद की मान्यता प्रदेश सरकार ने रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंगलवार को इससे जुड़े उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग की जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बीपीएड पाठ्यक्रम की फर्जी और बैक डेट में मार्कशीट व डिग्रियां जारी की गईं। इनका प्रयोग राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस की जांच व शासन स्तर पर गठित जांच समितियों की आस्था में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं हैं। वहीं इस मामले में कुलाधिपति व कुलसचिव की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंत्री ने बताया कि जेएस विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम की विधिनियम बाराओं का उल्लंघन किया गया है। इसमें डिग्री देने की शक्ति के दुरुपयोग, संगठित अपराध के रूप में फर्जी अंकतालिकाओं व डिग्रियों का वितरण, आवश्यक भूमि मानक का पालन न करना तथा उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य विवरण उपलब्ध न कराना भी शामिल है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है।

सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए ध्वस्त होंगे जर्जर भवन

वाराणसी में बनने वाले 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय जिला चिकित्सालय परिसर में पहले से मौजूद 11 जर्जर और निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वाराणसी में 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बन रहा है। यह अस्पताल 315 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से बनेगा। इसका निर्माण कार्य चार वर्षों में पूरा होगा। यह परियोजना 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार (लगभग 189 करोड़ रुपये) और 40 प्रतिशत राज्य सरकार (लगभग 126 करोड़ रुपये) से पूरी होगी। इस अस्पताल के बनने से वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल के सभी जिलों के मरीजों को अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

प्रदेश में पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर बदले नियम

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस फैसले से जहां पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, वहीं किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। योगी सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ इंडिंग लिविंग की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

पैतृक संपत्ति के बंटवारे में बड़ी सहूलियत

योगी सरकार के निर्णय के तहत अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए मात्र 10,000 रुपये में रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इसमें 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क शामिल होंगे। यह व्यवस्था तीन पीढ़ियों से अधिक पारंपरिक वंशजों के बीच लागू होगी। बंटवारा केवल पैतृक संपत्ति का ही किया जाएगा, जिसमें कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं।



गोशालाओं में सर्दी से बचाव के नहीं हैं पर्याप्त इंतजाम, टिडुर रहे गोवंश

गोशालाओं की व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं होती



राजधानी लखनऊ मलिहाबाद व बीकेटी सहित राजधानी के आठों विकासखंडों में संचालित सरकारी गोशालाओं में निराश्रित गोवंशों का बुरा हाल है। इस कड़के की सर्दी में भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से गोवंश टिडुरने को मजबूर हैं। ऊपर से टिनशेड डाल दिया गया है, और तिरपाल भी दिखावे के लिए टिन शेड्स के चारों तरफ लटकवाया गया है। जिससे इस समय चल रही शीतलहर से गोवंशों को बचाने के लिए नाकामि साबित हो रहा है। बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विधान केसरी

की टीम ने बीकेटी विकासखंड के कठवारा, रैथा, इंदारा, सुबशीपुर, किशुनपुर में स्थित गोशाला की पड़ताल की, तो यह हकीकत सामने आई, यहां गंदगी की भरमार दिखाई दी, तथा खाने को मौके पर पुआल पड़ी हुई थी। वृहद गोशाला में गोवंशों के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की कुंडी बनी हुई है, इनमें ठंडा पानी भरा रहता

वंश अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते नजर आ रहे अधिकारी भले ही गोशालाओं की सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए दिशा निर्देश है। देते रहते हो लेकिन जिम्मेदार लोगों की अनदेखी एवं खाऊ कमाऊ नीति के चलते बुरा हाल है। कहीं कड़के की ठंड में इन गोशालाओं में संरक्षित गोवंश टिडुरने नजर आ रहे हैं तो कहीं सूखा भूसा खाकर अपना पेट भर रहे हैं। लगातार सूखा चारा खाने से गोवंशों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीण बताते हैं कि गोशालाओं की देखरेख करने वाले जिम्मेदारों की अनदेखी एवं कमाऊ नीति चलते इन दिनों गोशालाओं में संरक्षित गोवंश जहां कड़के की ठंड में टिडुरने को मजबूर हो रहे हैं जहाँ सूखा भूसा खाकर अपना पेट भर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा इस गोशाला में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में जांच आर अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है।

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

पंचायती राज विभाग ने जारी किया महिला सशक्तिकरण पर आधारित विशेष कैलेंडर

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों में उनकी वास्तविक एवं सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित विशेष कैलेंडर जारी किया गया है। यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं बल्कि पंचायतों में महिलाओं की

भूमिका को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है। कैलेंडर के माध्यम से संदेश दिया गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाएं केवल नाम की प्रधान या प्रतिनिधि न रहें, बल्कि विकास कार्यों और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। यह पहल महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने, अपनी बात मजबूती से

रखने और पंचायत संचालन में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। कैलेंडर ग्राम पंचायतों, पंचायत भवनों एवं विभागीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जनप्रतिनिधियों आम नगरिकों में महिलाओं की सहभागिता को लेकर सकारात्मक सोच विकसित हो सके। पंचायती राज विभाग का यह प्रयास ग्रामीण

स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने और निर्णय प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि नारी शक्ति की नई उड़ान, गांव बदल रही महिला प्रधान केवल एक पहल नहीं, बल्कि मजबूत लोकतंत्र की नींव है। जब पंचायतों में महिलाएं सशक्त होंगी और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय

एआईएफ सेक्टर में सराहनीय कार्य के लिए यूपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में रीजनल कान्फ्रेंस समारोह का आयोजन आज चंडीगढ़ में किया गया, जिसमें यूपी राज्य को 'बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट' का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत प्रदेश में 13384 प्रोजेक्ट्स हेतु 8394.17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है जिसमें से 12602 लाभार्थियों को 5754.37 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा फसलोपरान्त हानियों को कम करने के लिए तथा कृषि अवस्थापना के विकास हेतु अगस्त 2020 से कृषि अवसंरचना निधि योजना को प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये तक के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत व्याज उपादान प्रदान किया जाता है।

विकसित भारत-गारंटी कानून 2025 गरीबों के लिए हितकारी: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और जनकल्याणकारी नेतृत्व में 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025' का क्रियान्वयन ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून गरीबों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को गति देगा। मोर्य ने बताया कि इस कानून के तहत 125 दिन का नियमित कार्य सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका का मजबूत आधार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्वरोजगार और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर केंद्रित है। इसके माध्यम से युवाओं को नवीन तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे



ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यह कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोर्य ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के प्रत्येक ग्राम तक रोजगार और आजीविका के अवसर पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की यह पहल आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास को नई दिशा देगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री कुंजेश पाठक, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता एवं विधायक राजपाल सिंह बालियान तथा कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और अनिल कुमार की उपस्थिति रही। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश इस कानून के क्रियान्वयन में देश के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेगा।

लखनऊ में भाजपा महानगर अध्यक्ष के साथ मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने पार्टी केसराबाग कार्यालय पर मंडल अध्यक्षों और मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रथम ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रिंट आउट बूथ वार मंडल अध्यक्षों को सौंपा

विधानसभा स्तर पर बैठक की जिसमें बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की और आवश्यकता अनुसार भरे जाने वाले फॉर्म वितरित कराये। इस दौरान नीरज सिंह ने कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी का नाम छूट रहा है तो जरूरी कागजात के साथ फॉर्म 6 और नाम या पते में सुधार के



लिए फॉर्म 8 भरवाना है। 6 फरवरी से पहले अपना दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु

वोट लिस्ट निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, ऐप और बीएलए के पास भी उपलब्ध है लेकिन सुविधा के लिए इसका प्रिंट आउट दिया जा रहा है जिसको प्रत्येक बूथ पर गहन अध्ययन करके सभी पात्र मतदाताओं का नाम चेक करना है। मीडिया प्रभारी प्रवीण गंग ने बताया कि बैठक में मानसिंह, रमाशंकर त्रिपाठी, चेतन सिंह बिष्ट, घनश्याम अग्रवाल, टिकू सोनकर, सौरभ वाल्मीकी, लव कुश त्रिवेदी सहित मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री से मिले अयोध्या के महापौर

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महापौर ने अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में संचालित और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति से मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। बैठक में नगर के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के

सुदृढीकरण और जनहित से जुड़ी योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या नगर निगम द्वारा स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने, सड़क व नाली निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के सौंदर्यीकरण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से करए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आगामी योजनाओं, विशेष रूप से बढ़ती

आबादी और श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विस्तार की आवश्यकता पर भी प्रस्तावित विकास कार्यों की साराहना की और महापौर द्वारा रखी गई मांगों व प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़ी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और अयोध्या के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

प्रदेश के राजस्व लेखपालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि अब प्रत्येक लेखपाल के हल्का क्षेत्र के गांवों के पंचायत भवन परिसर में ही एक कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लेखपालों को गांव में ही रुककर रात को विश्राम करना होगा, ताकि जनता से उनका संपर्क और अधिक सुदृढ़ हो सके। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से जारी पत्र के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27

में इस योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत भवन परिसर में स्थान की उपलब्धता को लेकर किए गए सभी की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी पूछा गया है कि जहां ग्राम पंचायत और हल्का की सीमाएं अलग-अलग हैं, वहां लेखपाल का मुख्यालय किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए एक गुगल शीट लिंक भी

जब शहर सो रहा था, तब आलमबाग पुलिस जगा रही थी भरोसा

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

जब शहर गहरी नींद में था, सड़कें सुनसान थीं और जनवरी माह की कड़कती ठंडी में आवागमन के सारे साधन ठप हो चुके थे—तभी आलमबाग पुलिस ने यह साबित कर दिया कि वहीं सिर्फ सख्ती की नहीं, भरोसे और संवेदना की भी पहचान है। देर रात साधन न मिलने से असहाय स्थिति में फंसे एक महिला और एक पुरुष के लिए आलमबाग पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आधी रात के समय दोनों व्यक्ति सुरक्षित घर लौटने का कोई साधन न मिलने के

कारण सड़क पर फंसे हुए थे। भय और असुरक्षा के माहौल में आलमबाग थाना पुलिस की गश्ती टीम ने उन्हें देखा और तत्काल मदद का फैसला लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र सरोज के नेतृत्व में पुलिस ने बिना किसी औपचारिकता के मानवीय जिम्मेदारी

भालुक होकर आलमबाग पुलिस व यूपी पुलिस का आभार जताया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएँ पुलिस और आमजन के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बनती हैं। प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र सरोज के नेतृत्व में आलमबाग पुलिस न केवल कानून-व्यवस्था संभाल रही है, बल्कि जरूरत के वक़्त आम लोगों के लिए संकटमोचक की भूमिका भी निभा रही है। यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि यूपी पुलिस केवल अपराध पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि अंधेरी रातों में आमजन के लिए उम्मीद की रोशनी भी है।

निभाते हुए दोनों को पुलिस वाहन से उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों का व्यवहार न सिर्फ शालीन रहा, बल्कि पूरी तरह संवेदनशील और भरोसे से भरा हुआ था। सुरक्षित घर पहुंचने के बाद दोनों लोगों ने राहत की सांस ली और

घने कोहरे के कारण आलू की फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना, किसान दवाई का कर रहे छिड़काव

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

लखनऊ जिले के बीकेटी ब्लाक क्षेत्र अंतर्गत इटौंजा क्षेत्र में कोहरा पड़ने तथा कड़के की ठंड होने से आलू की फसल में झुलसा रोग फैलने की संभावना बढ़ गई है व? मटर सरसों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। इससे किसान अपनी फसल को बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। इटौंजा क्षेत्र में केले की फसल के बाद किसान आलू की फसल का उत्पादन अधिक करते हैं। किसानों ने बताया कि 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किसानों ने आलू की फसल बो रखी है। इस वर्ष आलू का उत्पादन अधिक होने के आसार हैं पर घना कोहरा पड़ने के कारण तथा कड़के की ठंड होने की वजह से आलू में झुलसा रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। यदि आलू की फसल में झुलसा रोग लग जाता है तो किसान को आलू से भरपूर उत्पादन न मिलने से उनके इरादों पर पानी फिर जाएगा।

लेखपालों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब गांव में ही बनेगा आवास कक्ष, रात यहीं गुजारनी होगी

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

राजस्व परिषद ने जारी किया आदेश, पंचायत भवन परिसर में बनेगा एक कक्ष जिलाधिकारियों से मांगी गई आख्या



जिलों को उपलब्ध कराया गया है, जिस पर मांगी गई जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व परिषद ने इसे ग्रामीण स्तर पर राजस्व कार्यों को सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। अधिकारियों का मानना है कि गांव में रुकने से लेखपालों की पहुंच आम जनता तक सीधी होगी और नामांतरण, विरासत, नक्शा-खतौनी सहित अन्य राजस्व संबंधित समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। गौरतलब है कि लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों की अनुपलब्धता को लेकर शिकायतें उठती रही हैं। अब पंचायत भवन परिसर में आवासीय कक्ष बनने से लेखपालों की जवाबदेही और उपस्थिति दोनों सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

राजधानी की थाली में जहर: खीर में रेंगती चींटी, आलमबाग के श्री बालाजी ढाबा पर फूड विभाग का ताबड़तोड़ छापा

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। आलमबाग स्थित श्री बालाजी ढाबा में परेसी जा रही खीर में चींटी मिलने के सनसनीखेज शिकायत के बाद फूड विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अचानक छापेमारी की। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विजय प्रताप सिंह के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर विनोद कुमार जायसवाल और डॉ. आर.के. सिंह की टीम ने ढाबे पर पहुंचकर रसोई,

चार सैपल सील कर लैब भेजे गए, लाइसेंस-एनओसी की गहन जांच रिपोर्ट खराब आई तो ढाबा सील, संचालक पर कड़ी कार्रवाई तय



'मानकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं' फूड विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा कि लैब रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मानकों पर खरे न उतरने की स्थिति में भारी जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और ढाबा सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक खुले ढाबे बने सेहत के दुश्मन घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात तक खुले रहने वाले होटल-ढाबों पर नियमित जांच न होने से आम लोगों की सेहत से खुला खिलवाड़ हो रहा है। लोगों ने ऐसे प्रतिष्ठानों पर लगातार और सख्त छापेमारी की मांग की है। फूड विभाग ने संकेत दिए हैं कि राजधानी भर में अभियान तेज किया जाएगा और किसी भी कीमत पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा।

शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी का संकेत, संदीप सिंह ने दिया आश्वासन मानदेय वृद्धि सहित सभी मांगों पर काम जारी, जल्द सीएम देंगे घोषणा

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

बैसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी हर

समस्या और मांग का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि पर काम चल रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री इससे जुड़ी खुशखबरी देंगे।

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील मंत्री ने सभी से अपील की कि नकारात्मकता को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दें। विधायकों और संघ नेताओं की उपस्थिति इस अवसर पर एमएलसी और विधायक श्रीचंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह लोधी, देवेंद्र सिंह लोधी, देवेंद्र सिंह राजपूत, उमेश द्विवेदी, हरिओम वर्मा, अनीशी सिंह, मानवेंद्र सिंह और शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, महामंत्री सुशील कुमार तथा सगटन मंत्री कोशल कुमार सिंह भी उपस्थित थे और उन्होंने संबोधन दिया। सम्मान समारोह में मंत्री ने कही बड़ी बातें विश्वेश्वरैया साभागार में आयोजित सम्मान समारोह में संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को हित में गांभीर्य है। उन्होंने बताया कि जब कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव आया, तो मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों, रसोइयों और अनुदेशकों को इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। औपचारिकताएं पूरी कर इसे जल्द प्रभावी बनाया जाएगा।

एसआईआर में 2.67 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटे ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 1.08 लाख मतदाता 'अनुमोदित'

जन एक्सप्रेस। अमेठी

जनपद की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में 2 लाख 67 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि 1 लाख 8 हजार 493 मतदाताओं को अनुमोदित श्रेणी में रखा गया है। इन अनुमोदित मतदाताओं को शीघ्र नोटिस जारी किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने बताया कि एसआईआर से पहले जिले में कुल 14 लाख 46 हजार 528 मतदाता पंजीकृत थे। गहन सत्यापन के दौरान 2 लाख 68 हजार 241 मतदाता फार्म 'एएसडी' अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत श्रेणी में

पाए गए। हटाए गए नामों में 56 हजार 155 मृत मतदाता, 59 हजार 59 स्थानांतरित मतदाता तथा 23 हजार 439 स्थानांतरित महिला मतदाता शामिल हैं। इन सभी के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख 8 हजार 493 मतदाता ऐसे पाए गए, जिनका सत्यापन अभी पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए उन्हें 'अनुमोदित' श्रेणी में रखा गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुमोदित श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मतदाताओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत



नहीं किए गए, तो उनके नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही अब दावा-आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आगामी तिथि तक नए मतदाता, स्थानांतरण, नाम सुधार या विलोपन से संबंधित दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। सभी दावों और आपत्तियों

के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह माह को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां 06 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी तथा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी तक किए जाने हेतु आयोग द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा विभिन्न अहंता तिथियां एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई हैं। ऐसे मतदाता जो इन तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु फॉर्म-6 घोषणा पत्र सहित भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन नामावली में किसी प्रविष्टि में संशोधन मतदाता फोटो पहचान पत्र

के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हंकन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फॉर्म-8 घोषणा पत्र सहित भरकर संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रिकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं मतदाता सूची से मृतक, स्थानांतरित, डुल्लिकेट अथवा अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने हेतु भी निर्धारित फॉर्म भरकर जमा किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पंजीकरण अथवा किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के एप एवं वेबसाइट <https://voters.eci.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 घोषणा पत्र सहित भी भरे जा सकते हैं।

डीएम ने किया निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण

जन एक्सप्रेस। बलरामपुर



मंगलवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन द्वारा निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें उन्होंने परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर निर्माण कार्य को और अधिक तेजी से कराने के निर्देश दिए, ताकि परियोजना निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जा सके। शीतकाल को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के लिए अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए, जिससे श्रमिकों को

टंड से राहत मिल सके और कार्य सतत रूप से जारी रहे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने

विश्वविद्यालय के लिए अलग से किए जा रहे ट्रांसमिशन कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश संबंधित विभाग को प्रदान किए। इस दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले में शुरु हुआ मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम



जन एक्सप्रेस। बलरामपुर

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद की आलेख्य मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन किया गया है। यह मतदाता सूची जनपद के सभी मतदाताओं पर आम नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान एमएलके पीजी कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ना है।

युवा मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर

डीएम ने बताया कि अहंता तिथि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे

आम जनमानस को बाल विवाह के बारे में किया गया जागरूक

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार जनपद रायबरेली में चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत रायबरेली में हलवाई की दुकान, टेंट की दुकानों, कोतवाली में तथा सड़क पर जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें आम जनमानस हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आम जनमानस को बाल विवाह के दुष्परिणामों, उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को समाज में कहीं भी बाल विवाह न होने देने, खर्च बाल विवाह न करने एवं बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग को अवगत कराने की सलाह दी गई। उपस्थित सभी लोगों द्वारा समाज में व्यापक जागरूकता फैलाकर भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा रमेश मौर्य को ओबीसी विभाग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया

जन एक्सप्रेस। रायबरेली

रायबरेली ऊंचाहार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और ऊंचाहार निर्मासी रमेश मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए ओबीसी विभाग का नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा मध्य प्रदेश राज्य का प्रभारी बनाया गया जनपद के कांग्रेस के लोगों में तथा ऊंचाहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली लोगों ने रमेश मौर्य जी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं रमेश मौर्य को इसके पूर्व में बुदेलखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था मौर्य ने निष्ठापूर्वक कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम किया था। मौर्य के देख-रेख में कई वर्षों बाद कांग्रेस प्रचलनी ने झांसी-ललितपुर लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराई थीमौर्य की निष्ठा लगन और दक्षिण पिछड़े वर्ग में लोकप्रियता को देखते हुए शीघ्र नेतृत्व पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी नेता प्रियंका व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी एवं सांसद प्रियंका गांधी ने अमेठी के लोकप्रिय सांसद के एल शर्मा जी को सलाह पर उनकी



मजबूत करने का कार्य करूंगा इस मौके पर ऊंचाहार के वरिष्ठ समाजसेवी सेठ गुरु प्रसाद मौर्य डॉ0 आरपी मौर्य, ऊंचाहार के पूर्व चेयरमैन मो0 सख्त, एड0 सुरेश मौर्य नेता राम अभिलाषा मौर्यफौजी हरिश्चंद्र नारायण कुशधाम प्रथम रामगरीब पासी सलीम सिद्दीकी शानू मानसिंह पटेल सीबी मौर्य रामबाबू अम्बेडकर विदेशी पासी नरेन्द्र यादव दिनेश मौर्य बाबू राम साहू आशुतोष यादव नितिन मौर्य रामेश्वर निषाद वीरेंद्र पासी बबलू पासी जियालाल पासी कमलेश पासीइंद्रमोहन शेर बहादुर मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

शीतलहर का प्रभाव: कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय 14 जनवरी तक बंद

जन एक्सप्रेस। अमेठी

जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिया कि कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल चौदह जनवरी तक बंद रहेंगे। वर्तमान मौसम परिस्थितियों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे छोटे बच्चों के बीमार होने की आशंका बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्राइमरी से लेकर कक्षा आठवीं तक संचालित सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ठंड के कारण किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशित किया गया है, कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि ठंड और शीतलहर का प्रभाव कम होता है, तो आगे की स्थिति के अनुसार नए निर्देश जारी किए जाएंगे। अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों के हित में बताया है।

देश की आजादी के लिए सुख, मोह को त्यागने वालों को नमन: डीएम संजय चौहान

जन एक्सप्रेस। अमेठी

ताम्र पत्र विभूषित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को जिलाधिकारी संजय चौहान एवं पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक ने मूर्ति अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के मौके पर समूचे जनपद से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में विशेष जनों की मौजूदगी रही। देश की आजादी में अपने सुख, परिवार, मोह माया को दर किनार कर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले रण बांकुरों को हर देश भक्त नमन कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर जेल की रोटी खाने वाले पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिजनों के सम्मान में आज भी देश का हर व्यक्ति नतमस्तक है। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद के खरीना गांव निवासी स्वर्गीय पं. रामदुलारे द्विवेदी, उनकी धर्मपत्नी



स्वर्गीय सूर्यकुमार द्विवेदी की स्मृति में स्थापित प्रतिमा का भव्य अनावरण जिलाधिकारी अमेठी संजय चौहान पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक ने किया। मुख्य अतिथि डीएम संजय चौहान ने मूर्ति अनावरण के दौरान कहा कि देश का नाम लिए बगैर जिलाधिकारी ने कहा कि आज भी देश प्रेम का जज्बा मन में विद्यमान है, वक्त आने पर वो सामने आ जायेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों से कहा कि आप जो करती निकालकर लाए हैं,

उसे हम सब सम्भालकर ही रखेंगे। ताम्र पत्र विभूषित स्वर्गीय राम दुलारे द्विवेदी के पुत्र गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष चंद्र द्विवेदी, सुपुत्र सुधीर द्विवेदी, प्रपौत्र प्रखर द्विवेदी ने जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक को अंगवस्त्र, माल्यार्पण कर सम्मानित किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी, स्वतंत्रता संग्रामसेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह, जिलाउपाध्यक्ष परमानंद मिश्रा, चंद्र तिवारी, तहसील अमेठी

अध्यक्ष रमा निवास मिश्रा, तहसील महामंत्री वीरेंद्र प्रसाद तिवारी सहित समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया गया। गायत्री परिवार अमेठी के जिला समन्वयक डॉ त्रिवेणी सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार आज समाज के हित में विशिष्ट कार्य कर रहा है। देश और राष्ट्र की मजबूती के लिए समूचा गायत्री परिवार कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कार्यक्रम का संचालन गायत्री परिवार के जिला युवा समन्वयक डॉ प्रवीण सिंह दीपक ने कहा कि देश प्रेम ही एक ऐसा मंत्र है, जो हम सभी देशवासियों को नित नए आयामों तक पहुंचा सकता है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह, गायत्री परिवार के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला समन्वयक राधेश्याम तिवारी, राणा प्रताप सिंह, दिनेश तिवारी, अनिल मिश्रा, डॉ धर्मेन्द्र कुमार तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।

सब-जूनियर प्रदेश स्तरीय हॉकी टीम में पायनियर पब्लिक स्कूल के छात्राओं का चयन

जन एक्सप्रेस। बलरामपुर

जनपद बलरामपुर की अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की छात्राओं का चयन मंगलवार को सब-जूनियर प्रदेश स्तरीय हॉकी टीम में किया गया है। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को शहर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, बलरामपुर की 2 छात्राओं में आराध्या श्रीवास्तव व सुधा गौतम का चयन सब-जूनियर प्रदेश स्तरीय हॉकी टीम में हुआ है। दोनों छात्राएं जनपद स्तर एवं मण्डल स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चयनित हुईं, जिसके उपरान्त उन्हें प्रदेश स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु मेरठ के लिए रवाना किया गया। हॉकी संघ एवं खेल विभाग की ओर से चयनित छात्राओं को शुभकामनाएं



दी। हॉकी टीम के अध्यक्ष सलिल सिंह टीटू, उपाध्यक्ष डॉ0 एमपी तिवारी, सर्वेश सिंह, सचिव रश्मि सिंह एवं हॉकी कोच अभय सिंह ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबन्ध निदेशक डा0 एमपी तिवारी, उप प्रधानाचार्या शिखा पाण्डेय सहित समस्त अध्यापक

रायबरेली महोत्सव में सहनरपुर का फर्नीचर व साज-सज्जा का सामान लुभा रहा

रायबरेली। घर की सजावट हो या बिटिया की शादी। अगर आपको सझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कम कीमतों पर शादी और नक़सीरी से शूट फर्नीचर मिलेगा तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप रायबरेली शहर में चल रहे रायबरेली महोत्सव में पहुंच सकते हैं। शहर के जीआईसी मैदान में चल रहे रायबरेली महोत्सव में सहनरपुर के फर्नीचर का जलवा है। यह फर्नीचर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि यह कम कीमतों पर मौजूद है, यानी इसके लिए आपको अपनी जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं यह जो पुरा फर्नीचर है यह सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। इस लकड़ी की खासियत यह है कि यह लकड़ी जल्दी खराब नहीं होती है। इस पर कीड़े या दीमक नहीं लगते हैं। ऐसे में आप एक बार यह फर्नीचर खरीदें तो सालों साल तक आपको दूसरा फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एमएलके कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों ने बैठक के बाद प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस। बलरामपुर

मंगलवार को एमएलके पीजी कॉलेज के शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने संयुक्त बैठक कर वेतन भुगतान में देरी तथा अन्य समस्याओं को लेकर रोस व्यक्त किया है। शिक्षक संघ एवं शिक्षणेत्र कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र प्रचार्य को सौंपा है। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी, 2026 को अनुराह 12:45 बजे शिक्षक संघ एवं शिक्षणेत्र कर्मचारी संघ एम.एल.के. पी.जी. कॉलेज बलरामपुर की संयुक्त रूप से एक बैठक महाविद्यालय के पुस्तकालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में वेतन के भुगतान में विलंब होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। दूसरा महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के अनुमोदित ने जनपद में निष्पादन न होने के कारण उनमें गहरा क्षोभ व्याप्त है। इस क्रम में सर्वसम्मति से दोनों संघों (शिक्षक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारी संघ) के सदस्यों ने निर्णय लिया कि यदि 7 जनवरी 2026 तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं



कर्मचारी के वेतन सहित अन्य वित्तीय कार्य तथा प्रोन्नत संबंधी कार्य रुके हुए हैं जिस पर संघ के सभी सदस्यों ने खेद व्यक्त किया है। वेतन भुगतान तथा महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों से संबंधित पोषित शिक्षक, नियमित तथा अस्थाई कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णय का ज्ञापन महाविद्यालय प्रचार्य प्रोफेसर जे.पी. पांडे को शिक्षक संघ के महासचिव, डॉ शिव महेन्द्र सिंह ने विभिन्न अध्यापकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में दिया।

बढ़ी तो दिनांक 8 जनवरी 2026 से महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त समस्त कार्य तथा परीक्षा से संबंधित कार्य से अपने को शिक्षक एवं कर्मचारी विरत रखेंगे। बैठक में महाविद्यालय के समस्त नियमित शिक्षक, स्ववित्त पोषित शिक्षक, नियमित तथा अस्थाई कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में लिए गए निर्णय का ज्ञापन महाविद्यालय प्रचार्य प्रोफेसर जे.पी. पांडे को शिक्षक संघ के महासचिव, डॉ शिव महेन्द्र सिंह ने विभिन्न अध्यापकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में दिया।

परिवार नियोजन जागरूकता प्रचार वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जन एक्सप्रेस। बलरामपुर

जनपद बलरामपुर में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने मंगलवार को इतनी भी क्या जल्दी है? एसबीसीसी (सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन) कैम्पेन के तहत जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहन उम्मीद परियोजना के अंतर्गत जनपद के चयनित 150 गांवों में जाकर विवाह की सही उम्र, बच्चों में उचित अंतराल तथा गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग को लेकर समुदाय को जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्र



जन एक्सप्रेस



सम्पादकीय

खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को टेंगा दिखाने वालों को बड़ा झटका लगा है

यह फैसला उन आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का आधार है जिन्होंने दंगों में अपने घर, दुकानें और परिजन खोए। उनके लिए न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर फैसले जरूरी होते हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका आज भी राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को समझती है।

उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों- उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनबी अजादिया की पीठ ने हालाँकि इस मामले में अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। पीठ ने कहा, "अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पथ द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं- उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।" अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़काने और सुनिश्चित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है। उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद पानी दिया। यह बार बार साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी। ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग बन जाते हैं। जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को टेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वरों से एक तक गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपद्रवी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों पर पड़ेगा। अब यह ध्रम टूटोंगा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया अंततः उन्हें बचा लेगी। देखा जाये तो अदालत का सख्त रुख भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई को मजबूत करता है।

विचार एक्सप्रेस



आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर सदन में...

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। गृह मंत्रालय को भी सदन की कार्यवाही की शुरुआत आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर जोरदार हमलों के साथ हुई। भाजपा के विधायक अजय महावर ने सदन में इस... ▶ पृष्ठ 12 पर...

एक्सप्रेस आलेख

डिजिटल भारत की असली परीक्षा यही है कि वह अपने सबसे तेज दौड़ने वाले श्रमिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानित जीवन दे पाता है। तेजी से फैलती ऑनलाइन सेवाओं की दुनिया में गिग-वर्कर्स की कार्य-सेवाओं को अब अनौपचारिक नहीं, बल्कि नियोजित, मान्यताप्राप्त और सम्मानजनक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी मेहनत का उचित और सुनिश्चित भुगतान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा कोई दया नहीं, बल्कि उनका अधिकार है, जिसमें सरकार को निर्णायक हस्तक्षेप करना ही होगा। मुनाफ़े की अंधी दौड़ में लगी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को यह समझना होगा कि श्रम केवल लागत नहीं, बल्कि व्यवस्था की आत्मा है।

गिग-वर्कर्स: डिजिटल सुविधा की चकाचौंध में पसीने का अंधेरा



ललित गर्ग

शोषण की मानसिकता छोड़कर संवेदनशीलता और जवाबदेही अपनाए बिना कोई भी डिजिटल विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि गिग-वर्क को गरिमा, सुरक्षा और स्थायित्व के साथ विकसित किया जाए, तो यही सेवाएँ मजबूरी का प्रतीक नहीं, बल्कि रोजगार की एक आदर्श और मानवीय व्यवस्था बन सकती हैं, जहाँ सुविधा केवल उपभोक्ता को नहीं, सम्मान कामगार को भी मिले।

ऑनलाइन बाजार और त्वरित सेवाओं के इस दौर में गिग-वर्कर्स शहरी जीवन-व्यवस्था की वह अदृश्य रीढ़ बन चुके हैं, जिनके बिना 'दस मिनट में डिलीवरी' और 'एक क्लिक पर सुविधा' की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाजार आने-जाने के झड़ते से लोगों को मुक्त करने वाले ये युवा हर मौसम, हर समय और हर जोखिम में घर-घर सामान पहुँचाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके श्रम पर डिजिटल अर्थव्यवस्था की ऊँची इमारत खड़ी है, वही श्रमिक सबसे अधिक असुरक्षा, शोषण और उम्पेक्षा झेल रहे हैं। नये साल की पूर्व संध्या पर गिग-वर्कर्स द्वारा की गई हड़ताल ने भले ही देशव्यापी आपूर्ति-श्रृंखला को ठप न किया हो, लेकिन इसने उनकी बहलाल कार्य-परिस्थितियों की ओर देश का ध्यान अवश्य खींचा है। यह हड़ताल किसी राजनीतिक उकसावे का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते काम के दबाव, घटते मेहनताने, नौकरी की अनिश्चितता और सम्मान के अभाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अपना व परिवार का पोषण करने वाले इन युवा गिग-वर्कर्स को अक्सर सरपट दौड़ती मोटरसाइकिलों पर, भारी थैलों के साथ ऊँची इमारतों की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा जा सकता है। समय सीमा का दबाव इतना तीव्र होता है कि जरा-सी देरी पर आर्थिक दंड झेलना पड़ता है। दुर्घटना, बीमारी या तकनीकी गड़बड़ी-किसी भी स्थिति में उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। ग्राहकों का व्यवहार भी प्रायः अस्वेदनशील होता है। देर होने पर झिड़कियाँ, सामान में कमी निकालकर अपमान, कभी-कभी हिंसक व्यवहार और रेंटिंग के जरिये भविष्य की कमाई पर प्रहार-यह सब इनके रोजगार का हिस्सा है। इसके बावजूद औसतन 12-14 घंटे काम करने के बाद भी सात-आठ सौ रुपये की आय और वह भी बिना समुचित बीमा या सामाजिक सुरक्षा के एक गहरे शोषण की ओर इशारा करती है। गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले और स्वतंत्र रूप से छोटे-छोटे काम (गिग्स) करते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ऊबर, स्वीगी, जोमाटोएज या अन्य ऐप के जरिए मिलते हैं और इन्हें प्रति कार्य या प्रोजेक्ट के हिसाब से भुगतान मिलता है, न कि नियमित वेतन। इन श्रमिकों के पास कोई स्थायी रोजगार अनुबंध नहीं होता और वे खुद के बॉस की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा (जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन) जैसे लाभ नहीं मिलते। गिग वर्कर्स की चुनौतियाँ एवं मजबूरियाँ ज्यादा हैं, आय कम। आय की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी, बीमारी, दुर्घटना, पेंशन का अभाव, श्रम अधिक-भुगतान कम, कामकाजी घंटों और मजदूरी को लेकर अक्सर विवाद। गिग वर्कर्स गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं, जहाँ वे अपनी मज्जी से छोटे-छोटे, अस्थायी काम करके पैसे कमाते हैं, जो पारंपरिक 9-से-5 की नौकरी से अलग होता है। गिग वर्कर का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो



भारत सरकार द्वारा हालिया श्रम सुधारों में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान, आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर जैसी व्यवस्थाएँ एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम हैं।

आमतौर पर सेवा क्षेत्र में एक स्वतंत्र उकेदार या फ्रीलान्सर के रूप में अस्थायी काम करता है जो पारंपरिक नियोजित-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है। निस्संदेह, गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन की अपनी क्षमता दिखाई है। आज भारत में गिग-वर्कर्स की संख्या सवा करोड़ से अधिक है और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बेरोजगारी के बढ़ते दौर में पढ़े-लिखे युवा इस व्यवस्था में 'विकल्प' के रूप में नहीं, बल्कि 'मजबूरी' में प्रवेश कर रहे हैं। जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, वहाँ शिक्षित युवाओं का अस्थायी, असुरक्षित और सम्मानहीन श्रम-व्यवस्था में फँसना न केवल चिंताजनक, बल्कि शर्मनाक भी है। यह स्थिति बताती है कि हमारी विकास-नीतियाँ रोजगार की गुणवत्ता पर नहीं, केवल संख्या पर केंद्रित हैं। गिग-वर्कर्स की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कंपनियाँ उनसे पूरा काम लेती हैं, लेकिन उन्हें पारंपरिक नियोजित-कर्मचारी संबंध के दायरे में स्वीकार नहीं करतीं। उन्हें 'स्वतंत्र कामगार' कहकर नियुक्ति, स्थायित्व, बीमा और न्यूनतम वेतन जैसी जिम्मेदारियों से बचा जाता है। हायर एंड फायर की नीति, एल्गोरिदम आधारित नियंत्रण, रेंटिंग सिस्टम और प्रोत्साहन के नाम पर लालच-ये सब मिलकर एक ऐसी अदृश्य जकड़न पैदा करते हैं, जिसमें श्रमिक स्वतंत्र दिखता है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह नियंत्रित

होता है। हड़ताल के दौरान भी अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर या ऑर्डर बढ़कर श्रमिक एकता को कमजोर कर दिया जाता है। 31 दिसंबर को एक प्रमुख खाद्य वितरण कंपनी द्वारा रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किया जाना इसी विडंबना को उजागर करता है। हाल के दिनों में संसद में भी गिग-वर्कर्स के शोषण का मुद्दा उठा है। सांसद राघव चड्ढा और मनोज कुमार झा जैसे नेताओं ने इस वर्ग की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिलाया है। यह स्वागतयोग्य है, क्योंकि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जब तक इन श्रमिकों की आवाज शामिल नहीं होगी, तब तक सुधार अधूरे रहेंगे। भारत सरकार द्वारा हालिया श्रम सुधारों में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान, आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर जैसी व्यवस्थाएँ एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रावधान वास्तव में गिग-वर्कर्स के जीवन में ठोस बदलाव ला पाएँगे? या फिर ये केवल कागजी सुधार बनकर रह जायेंगे? जब तक न्यूनतम आय, कार्य-घंटों की सीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक इन सुधारों को परिवर्तनकारी नहीं कहा जा सकता। 31 दिसंबर की हड़ताल भले ही पूरी तरह सफल न रही हो, लेकिन वह नैतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह जायज़ थी। यह हड़ताल व्यवस्था को बाँधने करने से अधिक, व्यवस्था के भीतर छिपे अन्याय, शोषण की वृत्ति एवं दोगलेपन को उजागर करने का प्रयास थी। गिग-वर्कर्स ने यह संदेश दिया कि वे केवल 'डिलीवरी बॉय' नहीं, बल्कि श्रमशील नागरिक हैं, जिनके अधिकारों की अनदेखी अब और नहीं की जा सकती। निश्चित ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य गिग-वर्कर्स के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि नीति-निर्माता, कंपनियाँ और उपभोक्ता-तीनों अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करें। कंपनियों को लाभ के साथ जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी, सरकार को कानूनों का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा और उपभोक्ताओं को सुविधा के साथ संवेदनशीलता भी अपनानी होगी।



किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरूरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज का कौन सी दशा चलने से टाइन नौ चल रही है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलवार है, यही शुभकालना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के पौर्णिमा के अनुसार जानें। अगर आप आज वालन खरिदने का विचार कर रहे है या आज कोई नया व्यापार करना कर रहे है, गृह प्रवेश कर रहे है, गृह निर्माण कर रहे है, पार्टी खरिद रहे है, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, वही हमारी ओर से शुभ माना जानना है।

तिथि:	पंचमी 06:33 तक
नक्षत्र:	नभ 11:56 तक
पक्ष:	शुक्ल
वार:	मंगलवार
योग:	आसुष्मान, 06:34
सूर्योदय:	07:15
सूर्यास्त:	17:40
चंद्रमा:	कर्क राशि में
राहुकाल:	12:27-13:46
शुक्र की संवत्:	2082
शक संवत्:	1947
मास:	भाद्र
शुभ मुहूर्त:	कोई नहीं

जन एक्सप्रेस

रहे हैं कुछ कुछ भाग !
*आया ऐसा मौड़ है।
रहे हैं कुछ कुछ भाग ??!!
हो रही घटनाएँ।
लगी जैसे आग !!
जिधर हवा है चलती।
उधर ही जाना धूम !!
धमाधौकड़ी मामला।
है मची अब धूम !!
खेल राजनीति का।
और चुनावी बेला।
कौन लेगा जोखिम।
तय्यो रहना अकेला !!
खिचड़ी है पकानी।
सकट समझदार !!
होगी हर पल कोशिश।
बनै असरदार !!*



- कृष्णरंज राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

वर्कआउट के बाद नहीं आ रही है नींद? हो सकते हैं इसके 5 बड़े कारण

अच्छी और गहरी नींद आ जाए, तो सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस महसूस होती है। इससे पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और खुशी का एहसास भी बना रहता है। यही नहीं, अच्छी नींद अक्सर लोगों की प्रोडक्टिविटी में भी सुधार करती है। विशेषज्ञ तो यह भी कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अच्छी नींद लेते हैं, वे रचनात्मक काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिस दिन आप हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, उस दिन नींद आने में दिक्कत होती है? असल में ऐसा होता है और इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।

हार्मोन पर असर: हैवी वर्कआउट करने के वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता और शरीर के तापमान पर भी असर नजर आता है। यहां तक कि पसीना भी काफी ज्यादा आता है। ऐसे में शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है। खासकर, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन प्रभावित होते हैं। ये दोनों हार्मोन आपको एक्टिव रखते हैं और एनर्जी का स्तर भी बढ़ाते हैं। इसलिए, हैवी वर्कआउट के बाद नींद नहीं आती है।

बॉडी का टैम्परेचर बढ़ना: क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद आने के लिए बॉडी टैम्परेचर का कम होना जरूरी है,



जबकि हैवी वर्कआउट करने की वजह से बॉडी का टैम्परेचर बढ़ जाता है। यह भी नींद न आने का एक कारण होता है। विशेषज्ञों की मानें, तो अगर आप सोना चाहते हैं, तो इससे ठीक पहले वर्कआउट न करें।

हार्ट रेट का बढ़ना: स्लीप फाउंडेशन की मानें, तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट 60-100 बीपीएम होता है। नींद में हार्ट रेट करीब 20-30 फीसदी तक गिर सकता है। यह 40 से 60 बीपीएम के बीच आ जाता है। इसका मतलब है कि हैवी वर्कआउट करने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो आपको अच्छी नींद लेने नहीं देता है। यही नहीं, बल्कि हार्ट रेट की वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी भी प्रभावित होती है। ऐसा आमतौर पर स्ट्रेस और अन्य मेडिकल

कंडीशन की वजह से हो सकता है।

डिहाइड्रेशन: हैवी वर्कआउट करने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड भी होती है। अगर आप सोने से पहले खुद को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो आपको कई अन्य परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना या सिर घूमना आदि। ये समस्याएँ भी कई बार अच्छी और गहरी नींद नहीं लेने देती हैं।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर, कहने की बात ये है कि रात के समय सोने से ठीक पहले हैवी वर्कआउट करना सही नहीं होता है। इसके अलावा, सोने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका बॉडी का तापमान सामान्य हो, खुद को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें और गूड स्लीप हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। साथ ही, स्ट्रेस को भी मैनेज करें। इससे अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी।

खाली पेट वर्कआउट करने से क्या होता है? खाली पेट वर्कआउट करने से पैट तेजी से बन जाता है क्योंकि शरीर ऊर्जा के लिए जमा चर्बी का इस्तेमाल करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है।



योगेन्द्र योगी

नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में स्वच्छ जल पहुँच के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं तथा इसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है।

विकास को मुंह चिढ़ाती दूषित जल से होने वाली मौतें

केंद्र सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद देश में दूषित पेयजल जैसी बुनियादी समस्याएँ विकास को मुंह चिढ़ा रही हैं। देश में स्वच्छता में नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी से पीने से आठ लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब सौ लोग बीमार हो गए। यह तस्वीर बताती है कि देश में पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान अभी कोसों दूर है। सरकारें आंकड़ों के जरिए बेशक कितनी ही उपलब्धि का दावा कर लें किन्तु जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120 वें स्थान पर है और देश के लगभग 70 प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित हैं। इंदौर में जो हुआ उसने ये शक पैदा कर दिया है कि देश में कहीं भी ऐसी 'जहरीली मौत' की सपनाई हो सकती है। ऐसा तब होता है जब स्रोत नियंत्रण और मानक भुला दिए जाते हैं। भारत में सपनाई डॉटर की गुणवत्ता और पाइपलाइनों के रखरखाव को लेकर

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा मूल्यांकित भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 जिलों को 'अति-दोहित', 22 जिलों को 'गंभीर' और 69 जिलों को 'अर्ध-गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 16 अति-दोहित जिले हैं। पंजाब में 19 अति-दोहित और 1 गंभीर जिला है।

मानक तय हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सप्लाई वाले पानी के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स तय करता है। गाइडलाइंस कहती हैं कि उपभोक्ता के नल तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एजेंसी की जिम्मेदारी है। फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट। गाइडलाइंस के मुताबिक पाइपलाइनों को 30 से 50 वर्ष के अंदर बदला जाना जरूरी है। अगर बार-बार लीकेज की शिकायत आती है तो बिना देरी किए पाइप बदला जाना चाहिए। इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है इंदौर की घटना के बाद इस पर सवाल उठ रहे हैं। जिस पर सफाई भी दी जा रही है। जुलाई 2022 में गंदे पानी से जुड़े आंकड़े लैसेट स्टडी में बताया गया कि भारत में करीब 1.95 लाख बस्तियों में लोग दूषित पानी पी रहे हैं। जिसकी वजह से साल 2019 में 23

लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। शहर ही नहीं गांवों में भी साफ पानी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। गंदे पानी में बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और हेवी मेटल्स जैसे खतरनाक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अशुद्ध पानी पीने से हैजा, पॉलिया, पेचिश, गले की बीमारी, टायफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। भारत में हर दिन बड़ी संख्या में लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है। कर्माजित डॉक्टर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूषित पानी गंद पानी पीने से हर साल दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक करीब 600 मिलियन लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है, जो देश की कुल आबादी का 40% है। दूषित पानी की समस्या से सबसे ज्यादा

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में पीलीभीत में व्यापक अभियान, जागरूकता के साथ सख्त कार्रवाई

132 चालान, 36 डगामार वाहनों पर कार्रवाई, हेल्मेट-सीट बेल्ट पहनने वालों का सम्मान

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत



जागरूकता अभियान के साथ सख्त कार्रवाई भी

जागरूकता के साथ-साथ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई भी की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कुल 132 चालान किए गए, जिन पर 1,63,500 रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित और नियमों का उल्लंघन करने वाले 36 डगामार वाहनों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनजीवन को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे स्वयं भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी किसी की जान बचा सकती है।

यातायात कर्मियों द्वारा किया गया। परिवहन विभाग के प्रचार वाहन के माध्यम से वाहन चालकों और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दो पहिया वाहन चालकों को हेल्मेट पहनने तथा चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। बिना हेल्मेट चला रहे दो पहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें एक

विशेष स्टिकर दिखाया गया, जिस पर लिखा था— मुझे मेरे परिवार की कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं हेल्मेट नहीं लगाता हूँ। इस संदेश के माध्यम से अधिकारियों ने हेल्मेट न पहनने के दुष्परिणामों को भावनात्मक ढंग से समझाया और बाद में यह स्टिकर उनके वाहनों पर चिपकाया गया। वहीं, हेल्मेट लगाकर चल रहे दो पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और उनसे अपील की गई कि वे



तेज रफ्तार कार ने गांव में मचाया कहर, तीन मासूम पिल्लों को कुचला, बच्ची बाल-बाल बची लापरवाह चालक फटार, ग्रामीणों में आ क्रोश, कार्रवाई की मांग



जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

जनपद के थाना गजरोला कला क्षेत्र के गांव अजीतपुर पटपरा में तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर मौत का कारण बन गई। गांव के अंदर तेज गति से दौड़ रही एक कार ने सड़क किनारे बैठे तीन मासूम कुत्ते के पिल्लों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान पास में खेल रही पांच वर्षीय बच्ची भी कार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना इतनी अचानक और भयावह थी कि गांव के लोग दौड़ते दौड़ते ही फरार हो गए। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक ने न तो वाहन रोका और न



ही पीछे मुड़कर देखा। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया।

बाल बाल बची बच्ची की जान, पिल्लों की मौत से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

हादसे के समय गांव निवासी सूरजपाल को पांच वर्षीय बेटी सड़क के किनारे खेल रही थी। कार की चपेट में आने से वह कुछ ही कदम दूर रह गई। बच्ची के सुरक्षित बच जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह घटना गांव में तेज रफ्तार वाहनों के बढ़ते खतरे को उजागर कर गई। घटना के बाद पिल्लों की माँ मौके पर ही मंडराती रही, जिसे देखकर ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ ही देर में सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त

कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के भीतर से तेज गति से वाहन निकालना आम बात हो गई है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है।

प्रशासन से सुरक्षा इंतजामों की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में स्पीड ब्रेकर लगाने, चेतावनी संकेतक बोर्ड स्थापित करने और तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को भी दी गई है। ग्रामीण आरोपी वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए परिवार में चोरी-छिपे टगी, पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश

साइबर टगी में मुख्य आरोपी गड्ड और बाल अपचारी गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत



होल्ड कर दिए। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने बताया कि उनके पुत्र विशेष कुमार ने पिता का मोबाइल और आधार कार्ड चोरी कर फर्जी यूपीआई आईडी बनाई और साधियों आजम, अरबाज व भाई अमन के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।

इस तरीके से बैंक खाते से रकम अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी गई। पीड़ित के अनुसार, टगी से प्राप्त 2.59 लाख रुपये आपस में बांट लिए गए, जबकि कुल मिलाकर लगभग 9 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। साथ ही घर से दो सोने की अंगुठियां भी चोरी हो गईं।

गिरोह का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय

पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभियुक्त लंबे समय से फर्जी ऑनलाइन गेमिंग और वेटिंग साइट के जरिए टगी कर रहे थे। गिरोह में गड्ड नई साइट बनाकर एडमिन बनाता था, जबकि मुशाहिद तकनीकी संचालन करता था। अरबाज और आजम युवाओं को फर्जी साइटों से

जोड़कर रातों-रात अमीर बनने का लालच देते थे।

व्यूआर कोड और यूपीआई से रकम ट्रांसफर

गिरोह आरोपित व्यूआर कोड और यूपीआई के जरिए रकम डालवाकर विभिन्न खातों में ट्रांसफर करता था। कमीशन कटाने के बाद शेष राशि नकद या ऑनलाइन मुख्य संचालकों तक पहुंचाई जाती थी।

पुलिस टीम ने की सफल कार्रवाई

इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र कुमार, निरीक्षक के.वी., निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक तरुण कुमार, उप निरीक्षक विकास कुमार, आरक्षी ललित कुमार, आरक्षी विवेक कुमार और आरक्षी अजय कुमार शामिल रहे। पुलिस ने आजम तथा से अपील की है कि ऑनलाइन गेमिंग, निवेश या उच्च मुनाफे के प्रलोभनों से सतर्क रहें और किसी भी सदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाना को दें।

बीएलओ ने मतदाता सूची का प्रकाशन कराई, ग्रामीणों को कराया जागरूक

जन एक्सप्रेस। पूरपुर। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर ग्रामीणों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया। मंगलवार को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने अपने-अपने मतदेय स्थलों पर पहुंचकर भाग संख्या-79 और 80 के कम्पोजिट विद्यालय अमरैयाकला में मतदाता सूची का सार्वजनिक पाठ किया। बीएलओ कंचन देवी कुशवाहा और उमाशंकर ने ग्रामीणों को सूची बारी-बारी से दिखाकर उनके नामों की पुष्टि कराई। इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालयों तकियादीनारपुर, रुरिया सलेमपुर, खाता, महादिया, टांडा गुलाबराय और नवदिया टांडर आदि बूथों पर भी मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस मौके पर बीएलओ राजेश्वरी, उर्मिला देवी, शशीना नाज, रामनरेश, संदेश कुमार सहित सुपरवाइजर सुर्यप्रकाश गंगवार, भद्रकृष्ण कुशवाहा, मो0 फुरकान, मनीज कुमार, ऋषि संकसेना, विपिन दीक्षित आदि उपस्थित रहे और प्रकाशन का जायजा लिया। मतदाता सूची का प्रकाशन ग्रामीणों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता आगोश और नए मतदाताओं को जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद महाराज ने रामनगर जगतपुर में बूथ स्तरीय जनसंवाद कैम्प आयोजित किया

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

128 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामनगर जगतपुर में बूथ संख्या 289 और 290 पर बरखेड़ा विधायक एवं महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद महाराज द्वारा बूथ स्तरीय कैम्प का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीणों को प्रेरित किया, जिनका अभी तक मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है। कैम्प में पात्र लोगों से मतदाता फॉर्म भरवाकर जमा करने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि अधिक से अधिक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकें।

रमनगर शंड का भूमि पूजन, ग्रामीणों को सुविधा



कैम्प के उपरांत विधायक स्वामी प्रवक्तानंद महाराज ने ग्राम क्षेत्र में लगभग 24 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाले श्मशान शेंड की आधारशिला रखकर भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह श्मशान शेंड ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिससे अतिम संस्कार के दौरान सुविधा और सम्मानजनक जन



एक्सप्रेस। वातावरण उपलब्ध होगा। विधायक ने आश्चर्य किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी और सभी योजनाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएंगी।

ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों की रहीं उपस्थिति

इस अवसर पर ग्राम प्रधान कुन्दनलाल मोर्य, सोमपाल बर्मा, सत्यप्रकाश, रघुनन्दन, ओमप्रकाश मोर्य, प्रेमशंकर

गंगवार, युगल वर्मा, हेरेंद्र कुमार बर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कैम्प और विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम के समापन पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ अधिक से अधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्चर्य किया कि आने वाले समय में ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे।

पीलीभीत को नए साल की सौगात- दियूनी केंसरपुर में बनेगा आधुनिक रोडवेज बस स्टेशन

कैबिनेट से मिली मंजूरी, 9.21 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, दो वर्ष में पूरा होने की संभावना

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

नए वर्ष की शुरुआत में पीलीभीत जनपद को एक बड़ी बुनियादी सौगात मिली है। गांव विकास एवं चीनी मिलें राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के प्रयासों से दियूनी केंसरपुर में प्रस्तावित नवीन रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही अब इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में शासन को नवीन बस स्टेशन का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है।

9.21 करोड़ की लागत,

अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप, 300 किलो लहन नष्ट

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत। जनपद में अवैध शराब के काले कारोबार पर प्रशासन ने अब पूरी तरह सख्त रुख अपना लिया है। जहरीली कच्ची शराब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिकवाई करने वाले और युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वाले शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए बड़ा अभियान चलाया। आवकारी आयुक्त के निर्देशों और जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशन में आवकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को कलीनगर क्षेत्र में छापेमारी की। अभियान में आवकारी अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्र 1, 4 और 5 के निरीक्षक, अपने स्टाफ और थाना माधोटांडा पुलिस बल के साथ अवैध शराब के ठिकानों पर दौड़ दी गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से लगभग 75 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा शराब बनाने में सॉ फ्लावर कई भांडियों को ध्वस्त कर 300 किलो लहन नष्ट किया गया, ताकि पुनः अवैध शराब का निर्माण न हो सके। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया कि अब जनपद में अवैध शराब के कारोबारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कार्रवाई में आवकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत तीन अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए गए। मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में पूरनलाल पुत्र राममूर्तिवाल, गेदनालाल पुत्र स्व. छोटेलाल, रामवती पत्नी रमेश और मायादेवी पत्नी स्व. शरीलाल शामिल हैं। सभी आरोपी कलीनगर, थाना माधोटांडा क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह आमजन की जान के लिए गंभीर खतरा भी बन चुकी है। इस कारण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति लागू की गई है।



1.317 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित

नवीन रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण पर लगभग 921.90 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके लिए कचहरी के समीप स्थित दियूनी केंसरपुर क्षेत्र में 1.317 हेक्टेयर भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को हस्तान्तरित किया जाएगा।

दो वर्ष में पूरा होने की संभावना

परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार नवीन बस स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग दो वर्षों के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है। इसके निर्माण के बाद वर्तमान बस अड्डे पर

पड़ने वाले दबाव से भी राहत मिलेगी और शहर के यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

नवीन बस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके- विशाल वेंटिंग हॉल, आधुनिक शौचालय, कैटॉन, विभिन्न व्यावसायिक स्टॉल, यात्रियों की सुविधा के अनुरूप अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रोजगार के नए अवसर भी होने सुनिश्चित बस स्टेशन के निर्माण और संचालन से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

जंगल का राजा और मानव का संरक्षण, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाघों की कहानी

जन एक्सप्रेस। मुकेश कुमार



जिंदगी बिता रहे हैं। पीटीआर के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से अब तक 26 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं। इनमें से 12 बाघों को वापस जंगल लौटने का अवसर मिला, जबकि 11 बाघों को चिड़ियाघरों में भेजा गया। यह आंकड़ा केवल वन्यजीव संरक्षण का नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी संकेत देता है। सवाल यह उठता है कि क्या यह समाधान स्थायी है? चिड़ियाघरों में बाघों के लिए कैद जीवन किसी प्राकृतिक अधिकार से कम नहीं, और कभी-कभी उनकी मौत तक हो जाती है। वहीं ग्रामीण और पर्यावरण विशेषज्ञ दोनों ही मानते हैं कि यदि रेस्क्यू और निगरानी समय रहते न की जाए तो

मानव-वन्यजीव संघर्ष गहराता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का अनुभव यही सिखाता है कि जंगल का संरक्षण केवल बाघों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह मानव-जीवन की सुरक्षा, स्थानीय समुदायों की जागरूकता और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने तक का जिम्मा है। यही संतुलन सहेजकर ही जंगल का राजा और मानव समाज दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। केसरी और चंद्र जैसी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि संरक्षण केवल सुरक्षा और संख्या का खेल नहीं है। यह संवेदनशील निर्णय, जिम्मेदार प्रशासन और समाज की जागरूकता का सामंजस्य है। बाघ और इंसान, दोनों के लिए यही असली जीत होगी।

एक्सप्रेस खबरें...

बरखेड़ा में युवती से छेड़छाड़ का आरोप

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत। बरखेड़ा। कश्मे में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब एक हिंदू युवती से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई, जिसके बाद युवक को थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती और आरोपी युवक दोनों कश्मे के एक ड्रीमी कॉलेज में अध्ययनरत हैं। घटना के बाद कश्मे में इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चा होती रही। युवक की पहचान थाना क्षेत्र के दोलतपुर गांव निवासी के रूप में बताई जा रही है। मामला दो समुदायों से संबंधित होने के कारण पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मोर्चा संभाल लिया। किसी भी तरह की अपवाह या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने कश्मे में सतर्कता बढ़ा दी है। पीड़िता के पिता की ओर से थाने में लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना पुलिस का कहना है कि मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस युवती के बयान सहित कॉलेज से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है।

जमीन विवाद में ससुराल वालों ने युवक पर किया हमला

जन एक्सप्रेस। पूरपुर। घुंघवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव उदरहा में 5 जनवरी को ससुराल पक्ष द्वारा युवक जवाहर लाल पुत्र बिहारी पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार, युवक ने जमीन नाम कराने से इनकार किया, जिसके बाद ससुराल वाले राम प्रसाद पुत्र चेताराम, वीरपाल, वीरेन्द्र और जितन ने मिलकर उसे लाठी-डंडों से पीटा। जानकारी मिलने पर घायल युवक को तत्काल सीएससी पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी जयशंकर सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है।

सेहराम स्टेशन परिसर के दुकानदारों को नोटिस जारी किया

जन एक्सप्रेस। पूरपुर। मैलानी रेल प्लॉक के सेहराम रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित लगभग डेढ़ सौ दुकानों को खाली कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किया। नोटिस की जानकारी लगते ही दुकानदारों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके तहत इन दुकानों को हटाया जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके में दुकानदारों और आमजन में बेचैनी का माहौल बन गया है। रेलवे प्रशासन ने कहा कि नोटिस जारी कर दुकानदारों को नियम के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। वहीं, दुकानदारों ने आशंका जताई कि निर्माण कार्य के कारण उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है।



जालौन में खनन माफिया का नंगा नाच, मौन बैठा जिला प्रशासन

जन एक्सप्रेस | शत्रुघ्न सिंह

उरई। बुदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी इस समय खनन सिंडिकेट के खूनी पंजों में झटपटा रही है। कालपी तहसील क्षेत्र के क्योटवा (गाटा सं. 267, 268 खंड संख्या 3) में गिरीश गुप्ता पुत्र स्व. भगवान दास गुप्ता निवासी 126 खननयान नियंत्रण मानिक चौक थाना कोतवाली तहसील व जिला झांसी द्वारा कानून और पर्यावरण की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े करती है। गौरतलब यह है कि एनजीटी के सख्त निर्देशों को दरकिनारा कर बेतवा की छत्ती को मशीनों से खनन किया जा रहा है। नियमों के मुताबिक खनन एक सीमित दायरे में और मैनुअल तरीके से होना चाहिए, लेकिन क्योटवा खंड संख्या 3 में प्रतिबंधित लिफ्ट मशीनों का खुला तांडव जारी है। दिन के उजाले से लेकर रात के



अंधेरे तक यह मशीनों की गहराई से बालू निकल रही है। जलधारा के बीच किए जा रहे इस अंधाधुंध दोहन से नदी में 15 से 25 फुट गहरे जानलेवा गड्ढे बन गए हैं, यह गड्ढे आगामी मानसून में स्थानीय ग्रामीण और मवेशियों के लिए जल समाधि साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिला प्रशासन और खनन विभाग की भूमिका का है। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो साक्ष्य और ग्रामीणों की

लागतार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णी नौद रहस्यमय बनी है। क्या गिरीश गुप्ता कंपनी को कानून से ऊपर होने की अधोपिण्ट छूट मिली है। सैकड़ों ओवरलोड ट्रकों का अवैध परिवहन किसकी सहूलियत पर हो रहा है। क्या प्रतिबंधित मशीनों की गूँज तहसील और जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रही है। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी जालौन सनी कौशल के मोबाइल नंबर पर

मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

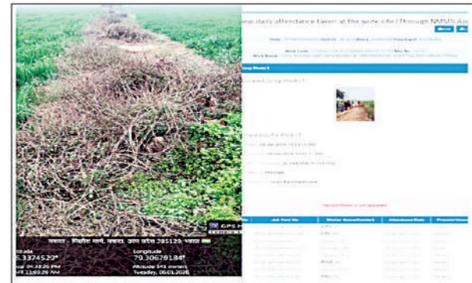
जन एक्सप्रेस | उरई

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चौरसी में किन्हीं कारणों के चलते मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चौरसी निवासी 26 वर्षीय देवेन्द्र पुत्र करन सिंह मजदूरी करता था। वह पिता से अलग घर के एक कमरे में रहता था और स्वयं की खाना बनाकर खाता था। सोमवार की रात को वह घर आया तो कुछ देर घर के बाहर खड़ा रहा और इसके बाद कमरे में जाकर मफलर का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। रात करीब 11 बजे उसका पिता बाहर आया तो उसने पुत्र के कमरे का दरवाजा खुला देखा और वह चला गया। जहां पर उसने पुत्र को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो वह दम रह गया और उसने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंचे चौकी प्रभारी फेक्ट्री परिया बूजेश सिंह ने शव को फंदे से नीचे उतारा और जांच पड़ताल के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

रामपुरा के पिचोरा में मनरेगा योजना के गूल खुदाई-सफाई कार्य में मिला भ्रष्टाचार

जन एक्सप्रेस | शत्रुघ्न सिंह

उरई/रामपुरा। ग्राम पंचायत पिचोरा विकास खंड रामपुरा में गूल खुदाई एवं सफाई का कार्य मनरेगा योजना द्वारा कराया जा रहा जिसमें फर्जी बाड़ा देखने को मिला। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि हमारे गांव में मनरेगा योजना द्वारा किया जा रहा गूल खुदाई का कार्य पूर्णता फर्जीवाड़ा कर कागजों पर दर्शाया जा रहा और धरातल पर किसी भी तरह का मजदूरी से कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा और वहीं विकास खंड से लेकर ग्राम प्रधान तक कार्य करने वाले अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त जो भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा दे रहे। वहीं ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना द्वारा गूल खुदाई का कार्य फर्जी चल रहा है जो विकास खंड स्तर पर कागजों में प्रतिदिन एनएमएमएस करके 57 मजदूरों की मजदूरी दिखा कर खाना पूर्ति की जा रही लेकिन मौके पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा हकीकत देखी जाए तो कहीं भी कोई गूल खुदाई नहीं हो रही है। मजदूरों को नहीं मिल रही है मजदूरी/ग्राउंड जो



की रिपोर्ट के तहत फर्जी एनएमएस के द्वारा निकाला जा रहा है रुपया मजदूरों को नहीं मिल रही है मजदूरी बन्बी से वीरेंद्र के खेत तक मास्टर रोल नंबर 6125 से 6148 तक 9 मास्टर रोल में 57 लेबर कार्यरत है। आईडी नंबर 3138001034/आईसी/721763 गूल खुदाई और सफाई बन्बी से वीरेंद्र के खेत तक मेट एवं प्रधान रोजगार सेवक सचिव की मिलीभगत से आज 06/01/2026 की रिपोर्ट मौके पर जाकर देखा गया, तो कहीं भी गूल खुदाई नहीं हो रही है और ना ही कोई वहां लेबर थी गांव वालों ने बताया की फर्जी पैसा निकाला जा रहा है पहले भी कई

कार्यों का प्रधान द्वारा फर्जी पैसा निकाला गया है अगर उच्च अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत की सही तरीके से जांच की जाए तो खुलेगी लाखों की पोत, ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा विकास कार्यों के नाम पर जमकर किया गया भ्रष्टाचार और सरकार की ज़िरो टोलरेंस नीति की जांचक धज्जियां उड़ाई गईं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की कि ग्राम पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की उच्च अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वही डीसी मनरेगा से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

कड़ाके की ठंड में आधी रात कोंच पहुंचे जिलाधिकारी रैन बसेरों से अलाव तक का लिया जायजा

जन एक्सप्रेस | उरई

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कड़ाके की ठंड के बीच कल देर रात कोंच तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक संवेदनशीलता का परिचय दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों, गौशालाओं एवं मंडी परिसरों का शीतकालीन व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा रैन बसेरों को समुचित व्यवस्था की गई है, अतः खुले में सो रहे निराश्रित,

श्रमिक एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। डीएम ने अलाव जलाने की निरंतरता, पर्याप्त ईंधन की उपलब्धता तथा रैन बसेरों में कंबल, प्रकाश, पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्थाओं को स्वयं परखा। उन्होंने गौशालाओं में पशुओं के लिए ठंड से बचाव हेतु की गई व्यवस्थाओं को भी परखा। कहा कि शीतलहर के दौरान प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील और सक्रिय है तथा जनपद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रात्रिकालीन भ्रमण नियमित रूप से करने और व्यवस्थाओं की सतत निगरानी के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम ज्योति सिंह, ईओ मोनिका उमाव आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

शहर को जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में प्रशासन का बड़ा कदम

जन एक्सप्रेस | उरई

शहर को जाम की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने कोतवाली उरई में शहर के प्रमुख व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा अतिक्रमण हटाने को लेकर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा हुई। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क मार्गों पर ठेले, खुमचे एवं अस्थायी अतिक्रमण के कारण जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसे देखते हुए वेंडिंग जॉन निर्धारित किए गए हैं, ताकि छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से रोजगार मिल सके और यातायात बाधित न हो। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे स्वयं



आगे आकर अपना-अपना अतिक्रमण हटाएं। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि कुछ दुकानदारों द्वारा फुटपाथों पर भी अतिक्रमण किया गया है, जिससे पैदल चलने वाले नागरिकों को कठिनाई होती है। ऐसे दुकानदार स्वेच्छ से फुटपाथों से अपना अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 8 दिनों के भीतर यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो इसके पश्चात पुलिस, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सख्त अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ करेगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि वर्तमान में अस्थायी रूप से बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। व्यापारियों द्वारा

दिए गए सुझावों पर नगर मजिस्ट्रेट को समीक्षा कर यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने प्रशासन के इस अभियान का पुरा समर्थन करते हुए कहा कि शहर को जाम से मुक्त करना समय की मांग है। इसके लिए अतिक्रमण हटाना अत्यंत आवश्यक है। व्यापारियों ने भरोसा दिलाया कि वे स्वयं दुकानदारों एवं अन्य व्यापारियों को जागरूक करेंगे, ताकि सभी लोग स्वेच्छ से अतिक्रमण हटाकर उरई को स्वच्छ, सुंदर एवं अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, सीओ सिटी अर्चना सिंह, व्यापारी दिलीप सेठ, संतोष गुप्ता, अरुण सहित अन्य व्यापारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भेड़ी बालू खदान पर ट्रक से कुचल कर खलासी की मौत

जन एक्सप्रेस | उरई

कदौरा थाना क्षेत्र में भेड़ी बालू खदान पर ट्रक से कुचलकर खलासी की मौत हो गई। कुरार थाना क्षेत्र के बेरी निवासी कमल पुत्र सुखलाल प्रजापति 19 वर्ष एक ट्रक में खलासी का कार्य करता है। मंगलवार को ट्रक चालक भेड़ी खदान में मोरम भरने के लिए गया था। तभी खदान में चालक ट्रक को बैंक कर रहा था, उसी समय वलीनर उसी ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां पर जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत

घोषित कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली तो उनमें कोहराम मच गया और वह मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह का कहना है कि घटना की सूचना फोन पर प्राप्त हुई थी। जिस पर तत्काल प्रभाव से घटना स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक जांच पड़ताल की गई और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रक की स्थिति, चालक की भूमिका और दुर्घटना के समय की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है।

भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस | हरदोई

शाहाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रभारी श्रीधर त्रिपाठी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और सेमिनार को लेकर सुरक्षा और सहयोग की मांग की है।



ग्राम समाज, रेलवे संपत्ति व जनमानस और बन जिलों तथा पर्यावरण की संरक्षा व सुरक्षा के प्रति जागरूक करने, मनोबल आत्मवान व राष्ट्रबल एवं राष्ट्रभक्त बढ़ाने का प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय पंचायत का आयोजन दिनांक नौ को पुणे (उड़ीसा) सागर टैक बीच में 11 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम दिनांक 13 व 14 जनवरी 2026 को हरियाणा चेरीटेबल सोसाइटी रोड न. 6 सागर द्वीप दक्षिण परसना पश्चिम बंगाल में 1 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक किया जाएगा

तीसरा कार्यक्रम जसीडीह रेलवे स्टेशन के निकट आम के बाग में जिला देवघर (झारखंड) में 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक किया जाएगा। राष्ट्रीय शिविर एवं पंचायत में समस्त कार्यक्रमों को बहुत ही शालीनता अनुशासित एवं शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाएगा। खेतिहर मजदूरों, किसानों, महिलाओं के हित में समबंधित प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण शिविर पंचायत स्थल पर सहयोग व सुरक्षा के लिए निर्देशित करने की मांग की है।

एसपी जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश

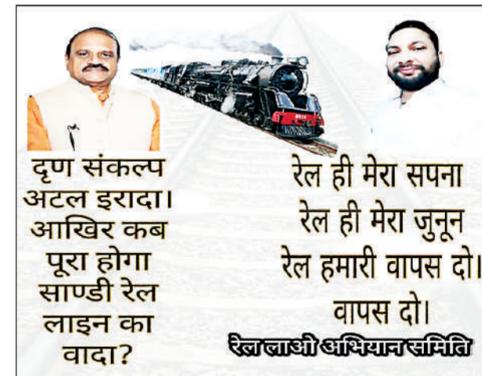
जन एक्सप्रेस/हरदोई। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान दूर-दराज से आए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं, जिन पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की जनसुनवाई से आम जनता में विश्वास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

सांडी रेल: वादों की पटरी पर दौड़ती रही राजनीति, नहीं पहुंची रेल लाइन

दशकों पुरानी मांग पर मिलता रहा आशासन, कागजों तक सिमटी प्रक्रिया

जन एक्सप्रेस | सांडी, हरदोई।

यहां रेल से जोड़ने का सपना अब विकास नहीं, बल्कि राजनीति का जुगल बनकर रह गया है। दशकों से जनता उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने इस सपने को धुंधला ही नहीं, लगभग अदृश्य कर दिया है। पूर्व सांसद अंशुल वर्मा के कार्यकाल में सर्वे पूरा हुआ, नक्शा बना और घोषणाओं की गूँज भी सुनाई दी। जनता ने मान लिया था कि अब रेल आने में देर नहीं। मगर अफसोस, फाहलें आगे बढ़ीं, सुर्खियां छर्रां, भाषण गूँजे-और वहीं सब ठहर गया। न पटरी बिछी, न इंजन आया। आज रेल लाओ अभियान समिति के पोस्टर सत्ता की चुप्पी पर कराटा तमाच है। सांसद से पूछा जा रहा है-आपका दृढ़ संकल्प आखिर कहाँ गया? क्या अटल इरादे चुनावी मंच तक ही सीमित थे? अगर इरादे पक्के होते, तो अब तक सांडी की



धरती पर लोहे की पटरी चमक रही होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सांडी की जनता सिर्फ वोट बैंक है? चुनाव आते ही विकास के वादे, चुनाव जाते ही गहरी खामोशी। क्या रेल मंत्रालय तक पैरवी करना सिर्फ भाषणों में ही आसान लगता है?

अब जनता तय करेगी-इस बार फिर खोखले आश्वासनों पर भरोसा किया जाए या उन प्रतिनिधियों से सीधा हिसाब माँगा जाए, जिन्होंने विकास को कागजों में कैद कर रखा है। क्योंकि अब सांडी को भाषण नहीं, रेल चाहिए।

ब्लॉक मुख्यालय पर पंचायत सहायकों की बैठक सम्पन्न

जन एक्सप्रेस/सांडी। सांडी ब्लॉक परिसर में मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर पंचायत सहायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी काजल ने की। बैठक में बीडीओ ने सभी पंचायत सहायकों को निर्देश दिए कि जिन पात्र परिवारों की फैमिली आईडी एवं आयुष्मान भारत कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र तैयार कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना से वंचित न रखा जाए। बीडीओ ने पंचायत सहायकों को अपने-अपने ग्राम पंचायतों में लाभियान चलाकर हूट्टे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी भी मौजूद रहे।

पूर्व विधायक पर गुंडों संग अवैध कब्जे का आरोप

जन एक्सप्रेस | आगरा

एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आगरा से सामने आया यह मामला उनकी ही पार्टी के नेताओं की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गजपुर चुंगी रोड स्थित शहीद नगर पुलिस चौकी के पास भाजपा के पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा पर खुलेआम गुंडागर्दी और अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। पीड़ित कृष्णा शर्मा, अनिल विश्वालोया, अमित कुमार, रणधीर सिंह और दीपू गर्ग का आरोप है कि श्रीजी कॉम्प्लेक्स के बाहर वॉल से लगे खोखों को हटाने के लिए पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा करीब 50-60 दबंगों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि दबंगों ने एक गरीब व्यक्ति के रेजी-रेटी का सहारा बना खोखों को पूरी तरह तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दीवार गिराकर और गेट हटकर पार्किंग की जमीन पर

जबरन कब्जा भी कर लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। नवंबर 2024 में भी उन्होंने इसी मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर खुलेआम तोड़फोड़ और कब्जे की कार्रवाई ने पुलिस की भूमिका को सवालों के घेरे में ला दिया है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि पूरी घटना शहीद नगर पुलिस चौकी के बेहद नजदीक हुई। आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी और सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही, लेकिन न तो दबंगों को रोका गया और न ही पीड़ितों की मदद की गई। काफी देर तक तोड़फोड़ चलती रही, पर पुलिस की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। पीड़ित परिवार ने मजबूर होकर मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की है। उनका आरोप है कि पूर्व विधायक और भाजपा नेता के राजनीतिक दबाव के चलते स्थानीय पुलिस कार्रवाई से बच रही है।

मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों पर हस्तक्षेप की मांग की

जन एक्सप्रेस | हरदोई

मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि बांग्लादेश में निवासरत हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे निरंतर अत्याचार, हिंसा, जबरन धर्मोत्तरण, संपत्तियों के विनाश एवं मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर आकृष्ट कराया जा रहा है। विभिन्न स्रोतों एवं प्रत्यक्ष रिपोर्टों के अनुसार वहाँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिससे निर्दोष नागरिकों का जीवन, सम्मान एवं सुरक्षा खतरे में है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ मानवाधिकारों एवं मानवीय मूल्यों का प्रबल समर्थक रहा है। ऐसे में हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार अपने



संवैधानिक एवं कूटनीतिक दायित्वों के अंतर्गत इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी हस्तक्षेप करे, बांग्लादेश सरकार से संवाद स्थापित करे तथा पीड़ित हिंदू समुदाय की सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास

सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाए। ज्ञापन में कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर मानवीय सहायता, राहत एवं संरक्षण से संबंधित उपायों पर विचार किया जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित राहत मिल

सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। संगठन ने इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए उचित दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव के निर्देशन में मुख्य अतिथि मौजूद राष्ट्रीय महासचिव नीलेश कुमार मंडल महासचिव अमित कुमार यादव कैलाश बाबू प्रतिनिधि ब्लाक प्रमुख हरेपालपुर, गौरव सिंह लखनऊ मंडल वरिष्ठ कानूनी सलाहकार जिलाध्यक्ष हरदोई सुमित पांडे, जिला उपाध्यक्ष शिवम पाट, जिला महासचिव रीतज पाल, ब्लाक अध्यक्ष शिवा राठौर राजन, अनुज पाल अंकित पाल जिलाध्यक्ष सीतापुर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ट्रेन में यात्रा कर रही महिलाओं की हमसफर बन रही 'मेरी सहेली'

जन एक्सप्रेस | आगरा

मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के दिशा निर्देशन व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पी. राज मोहन के निर्देशन में आगरा मंडल में आरपीएफ ने अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सहायता के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया है, इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ की 06 टीमों द्वारा कुल 44,856 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई है। रेलवे प्रशासन इन दिनों ट्रेनों में अकेली यात्रा कर रही महिलाओं को सुरक्षित महसूस कर रही है। इसमें महिला कारस्टेबल की ड्यूटी लाई है, जो आगरा मण्डल से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की जांच कर महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।

जनसम्पर्क अधिकारी कु. प्रशरित श्रीवास्तव ने बताया कि मेरी सहेली योजना के तहत अकेली महिला यात्रियों की यात्रा की पूरी जानकारी गाड़ी के प्रारंभ स्टेशन से ही अगले नामित स्टेशनों में रेलवे सुरक्षा बल की महिला बल को दी जाती है। जिससे स्टेशन में ट्रेन के आगमन होते ही मेरी सहेली की टीम ट्रेनों में जाकर महिला यात्रियों से संपर्क कर बात करती है। साथ ही उनको होने वाली परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में इन दिनों अकेली यात्रा कर रही महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसमें महिला कारस्टेबल की ड्यूटी लाई है, जो आगरा मण्डल से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की जांच कर महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।

मतदाता पंजीकरण अभियान-2026 का आगाज

डीएम ने युवाओं से की मतदाता बनने की अपील, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियों का निस्तारण

जन एक्सप्रेस | महाराजगंज



जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य प्रो. शिबन लाल सक्सेना की कर्मभूमि जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से मतदाता पंजीकरण अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान निर्मात्री सभा के विद्वान सदस्य की कर्मभूमि से अभियान की शुरुआत करना अत्यंत गौरव की बात है।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है, जिसके माध्यम से देश की नीति और दिशा तय करने वाली सरकार का चुनाव होता है। उन्होंने एसआईआर (विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण) अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया।

जिलाधिकारी ने बताया कि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियों का

निस्तारण किया जाएगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने छत्र-छात्राओं से अपील की कि वे बूथ पर प्रकाशित ड्राफ्ट रोल की जानकारी अपने परिवार व आसपास के लोगों तक पहुंचाएं और समय रहते दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए जागरूक करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ और

पारदर्शी मतदाता सूची स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। एसआईआर प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है, जिसे जनसहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि जनपद में एसआईआर प्रक्रिया सफलतापूर्वक संचालित हुई है। वयस्क मताधिकार संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। कार्यक्रम से पूर्व कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार मिश्रा ने

जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी का भुगमुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं देवी सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। संचालन नायब तहसीलदार देश दीपक तिवारी ने किया।

इस दौरान एसडीएम नन्द प्रकाश मौर्या, डीआईओएस प्रदीप कुमार शर्मा, तहसीलदार सदर पंकज शाही, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में छत्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पांडेयक विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 13 लोगों की बिजली कटी

जन एक्सप्रेस | देवरिया

एक मुश्त समाधान योजना का एक महाना पूरा होते ही विद्युत विभाग ने बकाएदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को पांडेय चक उपकेंद्र के अवर अभियंता अखिलेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने विद्युत चोरी में एफआईआर दर्ज की। टीम ने बैकुंठपुर में तीन, गौरा में दो, पांडेय चक चौहारे पर तीन, बिशुनपुर तिवारी टोला में दो और नगर पंचायत रामपुर कारखाना में तीन लोगों की बिजली काट दी।

विद्युत विभाग के बिजली काटते ही उपभोक्ता उपकेंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए। 13 उपभोक्ताओं में से पांच लोगों ने अपना बकाया बिल जमा कर दिया। अवर अभियंता अखिलेश गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों ने विद्युत बिल जमा कर दिया, उनकी बिजली बहाल कर दी गई। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा।

पांच माह से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर

जन एक्सप्रेस | देवरिया

गैस पाइप के चलते कई जगह जल निगम की मेन पाइप सहित अन्य सहायक पाइप भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पांच माह से 200 घरों की जल आपूर्ति बाधित है। इससे गांव के लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं।

सदर विकास खंड के पैकोली में करीब पांच माह पहले गैस पाइप डालने के लिए कार्यदायी संस्था की ओर से कार्य शुरू हुआ था, जिससे जल निगम की पाइप कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई। इससे करीब 200 घरों की जल आपूर्ति बंद हो गई। अभी कुछ ही घरों में जल निगम का पानी पहुंच रहा है। कार्यदायी संस्था की ओर से पाइप डालने के बाद गड्डे भर दिए। पानी लीकेज होने के बाद जब गांव के लोगों ने कार्यदायी संस्था को पानी के लीकेज की समस्या बताया तो जल निगम को अवगत कराने की बात कह कर पल्लू झाड़ लिए। पैकोली गांव के वीरेंद्र कुंवर ने बताया की पाइप की मरम्मत कर सलाहें चालू किया जाए, जिससे गांव वालों को शुद्ध जल मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने कई बार विभाग को सूचना दिया है।

मोबाइल टॉवर से चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़



जिले की बाधराय थाने की पुलिस ने मोबाइल टॉवर से बैटरी व केबल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक्सआईडी की दो बैटरी, दो पावर केबल के साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल भी बरामद किया है। बता दें कि बीते रविवार को थाना इलाके के कोरही गांव निवासी सन्तोष मिश्र जो भितरा में एक मोबाइल टॉवर पर देखरेख करने हेतु नियुक्त है। सन्तोष ने थाने पर तहरीर बताया कि बीते रविवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा टॉवर के गेट व ताले तोड़कर पावर केबल व दो बैटरियां चोरी कर ली गईं। सुबह जब जानकारी हुई तो युवक ने थाने पर तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की सरगमी से तलाश कर रही थी। एसपी दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी पंथमी व सीओ सदर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाधराय श्रवण कुमार नेतृत्व में एसआई विकास प्रधान व उनकी

पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गलगली मोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अभय पटेल, धीरज कुमार व विजय कुमार मौर्या जेठवारा थाना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई दो बैटरी, दो पावर केबल व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल बरामद किया है। पुलिस ने मोटर साइकिल को एमवी एक्ट में सीज कर दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि एक टुकड़ा पावर केबल भितरा मोबाइल टॉवर से व दूसरा टुकड़ा बदली का पुरवा के मोबाइल टॉवर से ताला तोड़कर हम

तीनों लोग मिलकर काट कर चुराकर लाये हैं। बदली पुरवा मोबाइल टॉवर से चोरी की गयी दो बैटरी के बारे में तीनों अभियुक्त एक साथ बताये कि साधन के अभाव में और पकड़े जाने के डर से रात में लाकर यहीं पुलिया के नीचे दोनों बैटरी छिपा दिया है जिसे अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया। एसएचओ बाधराय श्रवण कुमार ने बताया कि मोबाइल टॉवर से बैटरी व केबल चुराने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी की बैटरी व केबल के साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। मोटरसाइकिल को सीज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया गया।

ई-रिक्शा चालक से लूट के चार आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़



जिले की दिलीपुर थाने की पुलिस ने ई रिक्शा चालक के साथ हुई लूट में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि घटना में शामिल दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सोमवार को गिरफ्तार किया था। बता दें कि बीते शनिवार को दिलीपुर थाना इलाके के रामपुर आधारगंज में ई रिक्शा चालक सुनील कुमार से अज्ञात बदमाशों ने ई-रिक्शा को सूतसान स्थान पर रुकवाकर तमंचा एवं चाकू के दम पर ई-रिक्शा की बैटरी, मोबाइल फोन एवं सात सौ नकद छीन लिया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरगमी से तलाश कर रही थी। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में एएसपी पंथमी शैलेन्द्र लाल व सीओ पट्टी मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बलराम सिंह के

नेतृत्व में थाना दिलीपुर पुलिस टीम द्वारा थाना इलाके के चौहर्जन पुल के पास जंगल में बसीरपुर गांव में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद करते हुए जेल भेज दिया था। उसी क्रम में घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की पुलिस सरगमी से तलाश कर रही थी। उसी क्रम में एसओ बलराम सिंह ने भी टीम ने सुमित सरोज, सूरज उर्फ करन, रवि कुमार व रवि दुबे को लूट के एक मोबाइल फोन, नकदी व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल के साथ थाना इलाके के मिसिद्धीपुर मोड के पास से मंगलवार को

गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मुठभेड़ में दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद हम लोग डर गए थे और किसी घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में ही थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल चारों आरोपियों को मंगलवार को जेल भेज दिया। एसओ बलराम सिंह ने बताया कि ई रिक्शा चालक से हुई लूट के दो आरोपी सोमवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए थे। बाकी घटना में शामिल चार आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

अब नालों से नहीं गुजरेगी पानी की पाइपलाइन

जन एक्सप्रेस | देवरिया



शहर में 17 जगहों पर नालों के नीचे से पानी की पाइपलाइन गुजर रही है। इससे पानी की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर भी अगर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई तो गंदा पानी शहर के हजारों लोगों के घरों में पहुंच जाएगा।

इंदौर की घटना के बाद नगरपालिका और जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रशासन अब इन पाइपलाइन को नालों से बाहर निकालने की तैयारी में है। शहर में करीब 200 किलोमीटर की परिधि में जलकल की पाइपलाइन बिछे हुए हैं। इन पाइपलाइनों के सहारे करीब 40 हजार घरों में पानी की आपूर्ति होती है। इन पानी को लोग भोजन बनाने से लेकर पीने तक में उपयोग करते हैं। इसमें करीब 20 प्रतिशत पाइपलाइन जीआई पाइप और सीमेंटेड है।

कई बार पानी का स्तर काफी ऊपर हो जाता है, उस समय ये पाइपलाइनें गंदे पानी के अंदर होती हैं। इस दौरान अगर इनमें लीकेज हो जाए तो नाले का गंदा पानी इनमें समा जाएगा। इससे यह गंदा पानी घरों तक पहुंच जाएगा। जिससे बीमारी फैलने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। रविवार की शाम वीसी में प्रमुख सचिव ने किया सचेत - प्रमुख सचिव नगर विकास ने रविवार की शाम प्रदेशभर के नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों के साथ वीडियो कांफेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इसमें प्रमुख सचिव ने साथ गुजर रही सीवेज लाइन और पाइपलाइन की निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही नालों के अंदर से गुजरी रही पाइपलाइन की पहचान करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी दशा में दूषित पानी घरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। पानी की नियमित जांच, पानी की टंकियों की साफ-सफाई और क्लोरिनेशन के नालों का गंदा पानी इन पाइपलाइन को छूकर बहता है।

को मोहल्लों से जोड़ने के लिए नाला क्रॉस कराया गया है, जो नालों के अंदर से होकर गई हैं। शहर के स्थितिललाइन इलाके में सर्वाधिक पाइपलाइन नालों को क्रॉस करके गई हैं। इसमें कलकट्टे से लेकर गोरखपुर रोड ओवरब्रिज तक कई स्याट ऐसे हैं, जहां से पाइपलाइन गुजरी है। इंदौर की घटना के बाद जागे प्रशासन ने पूरे शहर में इस तरह की पाइपलाइन को खोजने का अभियान छेड़ दिया है। इस क्रम में अभी तक 17 स्थानों

को मोहल्लों से जोड़ने के लिए नाला क्रॉस कराया गया है, जो नालों के अंदर से होकर गई हैं। शहर के स्थितिललाइन इलाके में सर्वाधिक पाइपलाइन नालों को क्रॉस करके गई हैं। इसमें कलकट्टे से लेकर गोरखपुर रोड ओवरब्रिज तक कई स्याट ऐसे हैं, जहां से पाइपलाइन गुजरी है। इंदौर की घटना के बाद जागे प्रशासन ने पूरे शहर में इस तरह की पाइपलाइन को खोजने का अभियान छेड़ दिया है। इस क्रम में अभी तक 17 स्थानों

अंतर्जनपदीय व इनामिया बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़



जिले की फतनपुर थाने की पुलिस ने सर्विलांस टीम की सहायता से बीते सितम्बर माह में थाना इलाके के एक पेट्रोल पम्प पर हुई लूट की घटना से संबंधित एक इनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते सितम्बर माह में रानीगंज थाना इलाके के जयरामपुर गांव निवासी विवेक जायसवाल ने फतनपुर थाने पर तहरीर देते हुए बताया था कि थाना फतनपुर इलाके में कतौरीली में स्थित उसके पेट्रोल पंप पर 2 सितम्बर की रात लगभग दो बजे दो मोटरसाइकिलों से आए चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसके पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसकर वहाँ भोजन बना रहे कर्मचारियों से मारपीट करते हुए कर्मचारी त्रिभुवन के पास से पच्चीस हजार रुपये छीन लिए तथा बाहर तेल भरवा रहे ग्राहकों से भी मारपीट किये और फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार

अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। एसपी दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी पूर्वी शैलेन्द्र लाल व सीओ रानीगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष फतनपुर मनीष कुमार त्रिपाठी व उनकी पुलिस टीम ने सर्विलांस सेल के कास्टेबल सनोज

की मदद से प्राप्त सूचना पर पच्चीस हजार रुपये के इनामिया एक अन्तर्जनपदीय अभियुक्त उदय सिंह यादव को प्रयागराज जिले के शिवकुटी थाना इलाके के तेलियाराज में उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ प्रयागराज व प्रतापगढ़ में लूट, हत्या का प्रयास, मार-पीट, धमकी जैसे लगभग पांच मुकदमे दर्ज हैं। एसओ

स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 को मनाई जाएगी

जन एक्सप्रेस | कुशीनगर

स्वामी विवेकानंद की जयंती आगामी 12 जनवरी को जीवन ज्योति जागृति मिशन, तरया लक्ष्मीराम की तरफ से तरया लक्ष्मीराम में मनाई जाएगी। इसमें श्रद्धालु, बुद्धिजीवी और युवा जुटेंगे। यह बातें शहर के एक निजी होटल में सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान सेवरी के पूर्व विधायक नंदकिशोर मिश्रा ने कही। बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल जी मार्गदर्शन की भूमिका निभाएंगे। विजय अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, सांसद विजय कुमार दाबे, सांसद शशांक मणि त्रिपाठी आदि होंगे।

मुसीबत: वर्षों से पगडंडियों के सहारे आवागमन को मजबूर हैं सैकड़ों ग्रामीण

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़



जिले की पट्टी तहसील के मंगरौरा विकासखण्ड का एक ऐसा गांव जहां के ग्रामीण आज भी पगडंडियों के सहारे आवागमन को मजबूर हैं। इसके चलते उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि मंगरौरा विकासखण्ड के नरहरपुर ग्रामसभा अंतर्गत पूरेफुरमान के लोगों ने बताया कि लगभग डेढ़ किलोमीटर कच्चे रास्ते से होकर हम लोग रोजाना गुजरते हैं। गर्मियों में उड़ती हुई धूल व बारिश में कीचड़ से परेशान हम लोग आज भी पक्की सड़क के लिए भटक रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए शासन-प्रशासन से फरियाद न की हो। क्षेत्र के ग्रामीण वर्षों से फरियाद तो कर रहे हैं लेकिन सुनवाई के नाम पर मिला तो महज आश्वासन। गांव में

संचालित लालता प्रसाद इंडियन गैस एजेंसी के मालिक सुरेश बहादुर सिंह ने बताया आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे गांव में आवागमन की गम्भीर समस्या बनी हुई है। हम लोगों का आज भी कच्चे रास्ते से ही

आवागमन होता है। वहीं सिलेंडर लेकर आने-जाने वाले वाहनों को भी आवागमन में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अहाज सिंह व प्रकाश सिंह ने कहा कि बारिश के दिनों में तो हम लोगों को मोटरसाइकिल से निकलने में बड़ी समस्या होती है कई बार ग्रामीण गिरकर चोटहिल हो चुके हैं। वहीं त्रिपुरारी सिंह, इन्द्र प्रतिक सिंह, विश्राम, राजीव सिंह, अभिषेक सिंह ने बताया कि पक्की सड़क न होने के कारण बारिश के मौसम में आपातकालीन सुविधाओं का भी लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग किया कि उनके गांव तक अधूरे सड़क को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि उन्हें परेशानियों न उठनी पड़े।

वोटर बनने का मौका: मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का तहसील सदर में शुभारम्भ

जन एक्सप्रेस | प्रतापगढ़



जिले में मंगलवार को सदर तहसील में नए मतदाता बनाने का अभियान का शुभारंभ हुआ। एसडीएम सदर नैन्सी सिंह द्वारा तहसील सदर में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व माँ सरस्वती की प्रथिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। राजकीय बालिका इण्टर कालेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुति की गयी। इस अवसर पर एसडीएम सदर ने छत्र-छात्राओं व आमजनमानस से कहा कि छ: जनवरी से छ: फरवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म- 6 भरकर मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाताओं के नाम पंजीकृत किये जायेंगे अथवा पात्र व्यक्तियों के नाम जिनके नाम मतदाता सूची में छूट गये हैं, इसके लिये फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा। उन्होंने उपस्थित छत्र-छात्राओं से कहा कि अपने साथ-साथ अपने आस पास रहने वाले नव युवक/युवतियाओं तथा ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में नहीं है, उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाए, जिससे उनका भी मतदाता सूची में नाम जुड़ सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में

तीन अस्पताल संचालक और झोलाछाप पकड़ से दूर

जन एक्सप्रेस | कुशीनगर

तीन अस्पताल संचालक और एक झोलाछाप पुलिस की पहुंच से अभी भी दूर है, स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। तीनों संचालक अवैध तरीके से अस्पतालों का संचालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग की जांच में पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक इस खेल के पीछे शामिल कुछ सफेदपोशों का संरक्षण मिल रहा है, इसके चलते कार्रवाई के बाद भी अवैध अस्पताल संचालकों का नेटवर्क नहीं टूट रहा है। जिले में दो माह के अंदर ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत के चार मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की जांच में पता चला कि तीन अस्पताल अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जबकि एक का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन खामिया है।

पैमाइश के बाद भी विरोधी कर रहे जमीन पर कब्जा

जन एक्सप्रेस | कुशीनगर



तहसील सभागार में सोमवार को डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी केवल कुमार की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 77 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 11 मामलों का मौके से निस्तारण किया गया। बाकी शेष मामले 66 मामले संबंधित विभाग को निस्तारण के लिए भेज दिया गया। समाधान दिवस में मंदरहा निवासी लक्ष्मण रामभर ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरे जमीन का पैमाइश के बाद चारों तरफ पथर लगाने के बाद भी विरोधी राज्यस्व कानूनगो से मिलकर मेरे जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। कुड़वा दिल्लीनगर निवासी लखन यादव ने चक मार्ग पर मिट्टी भरवाने के लिए गुहार लगाई। कहा

कि गांव के ही कुछ कासकर मिट्टी कटवाकर बेच दिए हैं। काफी गड्डा हो जाने से रास्ता नहीं भरा जा रहा है। कई महीनों से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई करते हुए चक मार्ग भरवाने की मांग किया है। महुई खुर्द निवासी चंद्रशेखर पांडेय ने कसया न्यायालय में एक वाद के लिए 17 माह में अभी तक प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। रहसू जन्वूरी पट्टी से

महिलाएं पट्टे की जमीन पर कब्जा पाने लिए समाधान दिवस में पहुंची थी। जिन्हें डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिवपुर बुजुर्ग निवासी कांता मट्टेशिया ने अपने बैनामें की जमीन पर फजौरी तरीके से एक बैंक के शाखा प्रबंधक पर लोन पास करने का आरोप लगाया। कठरही निवासी धर्मंद चौरसिया ने विद्युत विभाग की ओर से करीब छह माह से बिजली मीटर में गलत रीडिंग आने की शिकायत दर्ज कराई।

डीएम ने राज्यस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। एसपी कुशीनगर ने उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है। उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। इस दौरान एसडीएम डा संतयज सिंह, नाथल, तहसीलदार धर्मवीर सिंह, बाबल, तहसीलदार सदीप कुमार, सीओ कुंदन सिंह आदि मौजूद रहे हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर हो पीएसपी का गठन : डीएमओ

फाइलेरिया उन्मूलन कार्य क्रम के तहत पूरे ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर होगा पीएसपी गठन

जन एक्सप्रेस। उन्नाव



उन्नाव जिला मलेरिया अधिकारी डीएमओ अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएचसी पुरवा सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्य क्रम के तहत सीएचओ व सगीनी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ब्लॉक के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर पीएसपी पेशेंट स्टेकहोल्डर प्लेटफॉर्म का गठन कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा 10 फरवरी से चलने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्य क्रम एमडीएम में पीएसपी के सहयोग से लोगों को दवा सेवन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी अर्चना मिश्रा ने कहा कि अभी ब्लॉक के पांच आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर

सहयोग से पीएसपी पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है, जो फाइलेरिया उन्मूलन कार्य क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब इसका गठन सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर किया जाएगा है। पीएसपी के माध्यम से सभी बीमारियों के प्रति क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने में बहुत ही सहायक होगा। पीएसपी के माध्यम से फाइलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता गतिविधियों, एमएमडीपी प्रशिक्षण, एमडीएम संस्था सीफार, पाथ, पीसीआई के जिला प्रतिनिधि सहित सगिनी मौजूद रहें।

इसके अलावा साल में एक बार 10 फरवरी से चलाने वाले एमडीएम अभियान में लगातार पांच साल तक दवा के सेवन से इस बीमारी से बचा जा सकता है। प्रशिक्षण में पीएसपी गठित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के पीएसपी सदस्यों ने अनुभव भी साझा किया। पीएसपी सदस्य सीएचओ मनीषा ने कहा कि जब से आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पीएसपी का गठन हुआ है फाइलेरिया सहित अन्य स्वास्थ्य जागरूकता कार्य क्रमों में अन्य हितधारकों का सहयोग मिल रहा है। पीएसपी सदस्य कोटेदार संत प्रसाद ने कहा कि सभी हितधारकों के सहयोग से जागरूकता कार्य क्रमों और एमडीएम अभियान में समुदाय को दवा को सेवन करने के लिए जागरूक करते हैं।

प्रशिक्षण में फाइलेरिया इंस्पेक्टर विशाल, बीसीपीएम इशाक अली, सहयोगी संस्था सीफार, पाथ, पीसीआई के जिला प्रतिनिधि सहित सगिनी मौजूद रहें।

हनुमान मंदिर समिति की आवश्यक बैठक

जन एक्सप्रेस। मोहनगढ़ी खीरी



हनुमान मंदिर समिति की आवश्यक बैठक मंदिर परिसर में प्रातः 9-30 पर सम्पन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता हरिओम गुप्ता ने तथा संचालन समिति के अध्यक्ष अतुल रस्तोगी ने किया, कार्यवाही श्री सुरेंद्र वर्मा ने लिखी, बैठक में मंदिर के वार्षिकोत्सव पर चर्चा हुई सर्वसम्मति से तय हुआ कि इस वर्ष वार्षिकोत्सव में पूज्य श्री डी0 रामनरेश शर्मा के द्वारा श्री हनुमान चरित की सुंदर कथा प्रस्तुत की जाएगी दिनांक 18,19,20 जनवरी 2026 अपराह्न 2 से 5 बजे तक, तत्पश्चात प्रसाद विरण किया जायेगा, इस अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार मंदिर की विशेष साज सज्जा की जायेगी, जिला संघचालक अमित भसीन ने अपने सम्बोधन में कहा कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है जिसकी स्थापना सन 1925 में नागपुर में हुई जो आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, संघ पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में कार्य कर रहा है जिसमें जिनमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबंधन, स्व0 आधारित जीवन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य बोध, आते हैं, हमारी दृष्टि ऋषि परम्परा की सनातन दृष्टि है, शताब्दी वर्ष में हम अपना कार्य विस्तार कर रहे हैं, कार्य की गुणात्मकता के साथ, इसी कड़ी में समाज परिवर्तन का केंद्र बने, हम विजया दशमी उत्सव, सामाजिक सद्भाव बैठक, व्यापक ग्रह सम्पर्क अभियान, ससशक्ति सम्मेलन, पंच चुके हैं और अब प्रत्येक न्याय पंचायत व बस्ती स्तर पर हम हिन्दू सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं जो जनवरी माह में सम्पन्न होगा इसी कड़ी में 14 जनवरी को स्थानीय पी डी भारती इण्टर कॉलेज मोहमदी में तथा 17 जनवरी को बंधन गेस्ट हाउस में हिन्दू सम्मेलन है आप सभी समर्थन समर्थित हो। सद्गुरु प्रकाश को गंधीतरा से लेते हुए अपने परिवर्तन, बंधु बंधनों, पड़ोसी व मित्रों के फार्म भर कर जमा हो गए यह चिंता करना। मंदिर समिति के अध्यक्ष अतुल रस्तोगी ने अपने सम्बोधन में कहा कि हम सभी प्रत्येक सप्ताह कुटुंब बैठक

करें, जिसमें परिवार के साथ भोजन, भजन, सत्संग, और संवाद करें, परिवार में साप्ताहिक अथवा पाश्चिमात्सहिक बैठक करें। किसी भी भोजन या खाद्य पदार्थ को, नवीन वस्त्र अलंकार आदि को ईंधर को अर्पित करके ही उपयोग करें, हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भ्रमण, भवन आसन हो। प्रेक्षक प्रसंगों के माध्यम से सोशल मीडिया का सदुपयोग अपने परिवार, समाज, व राष्ट्र हित में करें। बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए उन्हें समय दे तथा उनसे रचनात्मक कार्य करवाएँ। सेवा प्रदाता स्वयंसेवकों को उनके नाम या काम की अपेक्षा पारिवारिक सम्बन्धों जैसे काका, भ्राता, ताऊ, मामा, भाभी, बहन जी, मौसी, अम्मा, आदि आयु वर्ग अनुसार सम्बोधित करना, तथा बच्चों को भी यही अभ्यास कराना। जन्मदिन विवाह आदि का आयोजन भारतीय परंपरा के अनुसार हो, भोजन,वेशभूषा, आमंत्रण पत्र, रीति रिवाज स्वदेशी पद्धति के हों, आजकल वैवाहिक अवसरों पर पारंपरिक लैकगीतों के स्थान पर महिला संगीत के बेहद खर्चीले, और अभद्र आयोजन होने लगे हैं, यह सांस्कृतिक पतन का मंच पर प्रदर्शन है, यैसी ही हल्दी मेहंदी की पवित्र, भावपूर्ण, व वैज्ञानिक रीतियाँ भी ईवेंट बनकर रह गई है, यह विकास नहीं परंपराओं के छरण का विद्रु ही है, इससे बचने का दृढ़ आग्रह होना चाहिए। माझूलिक कार्य क्रमों में जब रिस्तदारों व परिवारों का एकत्रीकरण होता है तब सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी कुशल क्षेम पूछना व बच्चों को उनसे परिचित करवाना। माझूलिक कार्य क्रमों में कानफोडू

बाइक चलाते समय न उठायें मोबाइल फोन : अंकिता शुक्ला

जन एक्सप्रेस। बाराबंकी

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा नन्दलाल प्रभुदेवी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में सड़क सुरक्षा के प्रति स्कूली छात्र-छात्राओं व वाहन चालकों में जागरूकता लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ सहायक सम्भागीय अधिकारी प्रशासन अंकिता शुक्ला, सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक बलवंत सिंह यादव, यातायात प्रभारी रामयतन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में एआरटीओ श्रीमती शुक्ला ने छात्र-छात्राओं को कहा कि सड़क दुर्घटनाएँ केवल एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की क्षति होती हैं। जिन्हें यदि हम थोड़ी सी सावधानी, अनुशासन एवं जागरूकता से रोक सकते हैं। एआरटीओ ने हेल्मेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नरो की हातमें न वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा रोड़ सेपटी नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया।

तथा सड़क पर अनुशासन बनाए रखने, गलत दिशा में गाड़ी न चलाने और धैर्यपूर्वक नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक श्री यादव ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि युवा वर्ग समाज का सबसे सशक्त माध्यम है जो न केवल स्वयं नियमों का पालन करे। बल्कि अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करे। यातायात प्रभारी श्री यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। सुरक्षित ड्राइविंग, पैदल यात्रियों के अधिकारों का सम्मान, यातायात संकेतों का पालन और धैर्यपूर्ण व्यवहार ही सुरक्षित सड़कों की नींव है। इसके उपरान्त सभी को हमेशा सतर्क, जागरूक व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में प्रबन्धक सुशील कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, योगेश, शमशेर अली, शिवम, संजय, अंशुमान, सपना, अनामिका, नेहा सहित छात्र-छात्राव्यं व शिक्षक मौजूद रहे।

शिक्षित व्यक्ति समाज को देता है नई दिशा : प्रमोद तिवारी

जन एक्सप्रेस। बाराबंकी

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली श्रेष्ठ परीक्षा के परिणाम में जनपद के चयनित बच्चों का किया गया सम्मान होटल द जॉर्ज इन विकास भवन में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने उपस्थित बच्चों को माला पहना कर प्रोत्साहित सम्मान करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षा हमें जीवन जीने एवं संवारेने सजाने का बेहतरीन तरीका बताती है, शिक्षित समाज आने वाले भविष्य की रूपरेखा का निर्माण करता है। यदि हमारा समाज इसी तरह शिक्षित होगा तो अच्छे और बुरे की पहचान करने में आसानी होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदिदत्तनाथ को

बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ कार्य क्रम लाकर देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में बच्चों को चयन होने एवं पढ़ने के लिए यह व्यवस्था की है। जनपद के चयनित मेधावी छात्र विकास खण्ड देवा से 15 यूपीएस धौरमऊ हमेशा की तरह इस बार भी टॉप पर है जहां से 5 बच्चों का चयन हुआ है बहुत ही सर्वोच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा को भारत सरकार के माध्यम से सम्पन्न कराई जाती है जिसमें सम्पूर्ण भारतवर्ष के बहुत ही लक्ष्य प्रतिष्ठित टॉप सीबीसीई बोर्ड के निजी आवासीय विद्यालयों में इस परीक्षा परिणाम की रैंक के आधार पर ऑनलाइन काउंसिलिंग के बाद स्कूल अलॉटमेंट होता है जहां पर यह सेलेक्टेड बच्चे कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्राप्त करते

नीलकण्ठ मैदान से शुभारंभ हुआ नगर पालिका आपके द्वार अभियान का आगाज

उपजिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी ने द्वीप प्रज्वलित कर किया कैम्प का शुभारंभ

जन एक्सप्रेस। गोला गोकर्णनाथ खीरी



मंगलवार 06 जनवरी 2026 तृतीय स्थित नीलकण्ठ मैदान में आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर पालिका परिषद गोला के तत्वावधान में कैम्प का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी,तहसीलदार भीमचन्द्र एवं पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिकू ने फीता काटकर किया। नगर पालिका आपके द्वार अभियान में उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा कि, नगर की सम्मानित जनमानस को दफ्तरों के चकर नहीं लगाने पड़े इसके लिए नगर पालिका आपके द्वार अभियान चलाया गया है। हम सभी वार्डों में जाएंगे और निःशुल्क राशनकार्ड, पेंशन, विद्युत विभाग और नगर पालिका की समस्याओं का निस्तारण करेंगे।

एस डी एम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने कहा, पालिकाध्यक्ष के इस अभियान से सभी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा समस्याएं सुनकर उसका निराकरण करेंगे। नगर पालिका आपके द्वार अभियानका कैम्प वार्ड 06,19व 10 तीनों वार्डों से विद्युत विभाग की 06, वृद्धावस्था पेंशन की 41, दिव्यांग जनों की 03, विधवा पेंशन की 03, राशनकार्ड की 163 प्रार्थना पत्र आए। 07 जनवरी को कुहानर टोला स्थित गौशाला में प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक कैम्प रहेगा। इस अवसर पर सभासद राजेश अवस्थी, हर्ष अवस्थी, आनंद किशोर

गिरि भोली,जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा विनोद स्वर्णकार,लेखाकार मोहित अवस्थी, एस आई संदीप वर्मा, वरिष्ठ लिपिक अमित श्रीवास्तव, जेई सिविल अनिल कुमार यादव, जेई जलकर आदर्श मिश्रा, विद्युत विभाग से जेई धर्मेन्द्र चौधरी, टीजी दू मनीष सिंह, जितेन्द्र सिंह, खाद्य एवं रसद विभाग ऋषभ श्रीवास्तव अजय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग अजय कुमार पर्वशक, एकता सिंह कार्यालय सहायक, नगर पालिका से श्रवण कुमार मिश्रा, ऋषि कुमार, करणकांत, आशोक कुमार मिश्रा, विमलेश वर्मा आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को पकड़ा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा



जन एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी

नीमगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वारंटी/ वारंट/ सन्दिध अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत की गई।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गोलू उर्फ मोनू पुत्र रामप्रसाद, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम जमहौर, थाना नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। अभियुक्त के विरुद्ध मु0एम0 1788/24, अ0सं0 105/24 सरकार बनाम सुधीर आदि, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला

600 जरूरतमंदों को कंबल वितरित



जन एक्सप्रेस। मोहनगढ़ी खीर

गर्वापुर गांव में असफाक मंसूरी ने लगभग 600 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कार्य क्रम में गांव के बुजुर्गों को शाल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया कड़के की उंड के बीच, उन्होंने गांव में गरीब, असहाय, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को कंबल बांटे, विकलांगों को जैकेट, स्वेटर बांटे। जिससे गांव की जनता को सीधा लाभ मिल रहा यह सेवा अभियान गांव में संपन्न हुआ, जिससे जरूरतमंदों को उंड से काफी राहत मिली।इस अवसर पर असफाक मंसूरी ने कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने जोर दिया कि जरूरतमंदों के साथ खाद्य रहना ही सच्ची जनसेवा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह जन सेवा अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। ग्रामीणों ने उनके इन प्रयासों की सराहना की है।

एक्सप्रेस खबरें...

आमने-सामने हुई बाइकों की लड़ाई

जन एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी। सोमवार शाम लगभग 5 बजे सिसैया दखरेवा हाइवे पर सिसैया बाजार के पास कोहरे व भयानक ठंड के कारण दो बाइकों की आमने सामने भिड़त होने से तीन लोग घायल हुए जिन्हें प्राथमिक उपचार से लिए सी एच सी धौरहरा में भर्ती कराया गया। प्रास विवरण के अनुसार सोमवार शाम लगभग 5 बजे धौरहरा की तरफ से बाइक पर सवार होकर ईसांगर थाने जा रहे आरक्षी विष्णु कुमार 30 वर्ष व महिला आरक्षी सोनिया सागर 25 जते वक्त व सिसैया चौरहे पर बाइक एजेंसी में काम करके बाइक पर सवार होकर धौरहरा के मोहल्ल शुक्ला वार्ड निवासी 26 वर्षीय शिवम मिश्रा पुत्र आरक्षक किशोर की बाइकों की आमने सामने हुई भिड़त में सभी लोग घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सी एच सी धौरहरा में भर्ती कराया गया। समाचार प्रेषण तक चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल भेज कर दिया।

गन व्हाइंट पर मेडिकल ब्यवसाई से नगदी व मोबाइल की लूट

जन एक्सप्रेस। गोला गोकर्णनाथ खीरी। हैदराबाद थाना क्षेत्र के ममरी रोशननगर मार्ग पर सोमवार रात करीब 8 बजे बदमाशों ने एक मीडिया कर्मी अविनाश वर्मा को लूटने का प्रयास किया, उनके पीछे दूरसे बाइक चलाकर के साथ घटना को अंजाम दिया। प्रास जानकारी के अनुसार रोशननगर निवासी अविनाश चंद्र वर्मा गोला से अपने गांव रोशन नगर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने रोशननगर रोड पर बने नाले के पास बदमाशों ने उनके ऊपर उंडे से प्रहार कर दिया, लेकिन बाइक की रपौड तेज करके वह किसी तरह बच निकले। उनके पीछे बाइक से आ रहे से रोशन नगर निवासी अडिकल ब्यवसायी आशीष अग्निहोत्री से बदमाशों ने गन व्हाइंट पर रोक कर उनकी पर्स पर से रूखे दस रुपये व सैमसंग गैलैक्सी मोबाइल फोन लूट लिया। आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि गोला से वापस घर आ रहे थे हो ममरी रोशननगर मार्ग पर नाहरिया पर शाम करीब 8 बजे 5 या 6 बदमाशों ने घटना का इजाम दिया यहाँ तक बताया कि उण्डे से प्रहार किया, ममरी से जीप आ रही की रोशनी देख कर बदमाश लूट कर भाग गए। घटना की जानकारी हैदराबाद पुलिस को दी सूचना पर घटना स्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया। वहीं रोशननगर के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर पहले पुलिस सुरक्षा रहती थी, जो अब वह देखने को नहीं मिल रही पुलिस सहायता केंद्र भी था जो वह धराशाही कर दिया गया पुलिस सहायता केंद्र का नामो निशान हट गया, इससे वहाँ लोगों फिर लूट भय होने लगा,हैदराबाद एस ओ सुनील कुमार मलिक ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए दो बीट सिपाहियों की गस्त लाती थी मेरे सज्ञान मे नहीं है सुरक्षा के लिए यहाँ पर सिपाहियों को लगाया जायेगा।

विद्युत कर्मियों का चल रहा धरना तीसरी दिन हुआ समाप्त

जन एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी। मंगलवार को विद्युत कर्मियों का चल रहा धरना समाप्त हुआ लेकिन विद्युत संचिदाकर्मियों की लड़ाई जारी टीजी-2 कर्मचारियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच नयी सहमति के बाद भले ही खिल्ली कर्मियों ने हड़ताल खत्म कर दी हो। लेकिन विद्युत संचिदा कर्मियों की हक की लड़ाई अभी जारी है। संचिदा कर्मचारियों का कहना है कि हमारे जो साथियों को बिना नोटिस के हटा दिया गया है उनको वापस लिया जाए और काम की आश्चि तय हो। हम लोगों की यह मांग जब तक पूरी नहीं होती है, लड़ाई जारी रहेगी। बताते चले रामगोपाल की मौत का आरोप लगते हुए बीते तीन दिनों से चल रहा विद्युत कर्मियों का धरना समाप्त हो गया। संचिदा कार्यालय में पुलिस की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता ब्रह्मपाल कर्मचारियों से बातचीत के लिए पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी। अधीक्षण अभियंता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि मण्डल के बीच बनी सहमति में अधीक्षण अभियंता ने कर्मियों को अक्षेय काम कराना है, किसी को परेशान करना नहीं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में पांच कर्मचारी प्रतिनिधियों को कार्यालय बुलाया गया, जहां मांगों पर चर्चा हुई और सहमति बनी। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कार्य के घंटे निर्धारित करना, सार्वजनिक अवकाश पर कार्य के बदले साप्ताहिक अवकाश देना, बदले की भावना से कारवाई न करना, व्यवहार में सुधार और हर माह कर्मचारियों के साथ बैठक करना शामिल रहा। सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर रव, रामगोपाल को श्रद्धांजलि दी गई और प्रस्तावित कैंडल मार्च रखागत कर दिया गया।

दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस। बाराबंकी

सिरौलीगोसपुर। तीन दिन पूर्व विवाहिता की मौत के मामले में बदेसराय पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपों फरार हो गए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बदेसराय पुलिस ने 22 वर्षीय विवाहिता रुबी की हत्या के आरोप में पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी पति इस्तखार उर्फ चांदबाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हेंगिंग बताया गया है। मुकता 22 वर्षीय रुबी के भाई मुमताज ने पुलिस को बताया कि रुबी की शादी 8 फरवरी 2025 को ग्राम सरहरी निवासी इस्तखार उर्फ चांदबाबू से हुई थी। मुमताज के अनुसार, शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार स्विफ्ट डिजायर कार की

श्याम लाल की विरासत को बचाने का काम कर रही कांग्रेस : तुनज पुनिया

जन एक्सप्रेस। बाराबंकी



जब तक जनता जागरूक नहीं होगी हमें सत्याग्रह करते रहना होगा। जनता के मुँहों को लेकर सड़कों को गर्म करने की आज जरूरत है। ताकि हमारा लोकतंत्र जिन्दा रहे। श्यामलाल बाजपेयी ने संघर्ष और सत्याग्रह के जरिए राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज कांग्रेस पार्टी था कि यदि कार नहीं दी गई तो ससुराल वाले उसे मार डालेंगे। उसी दिन शाम 5:17 बजे रुबी के पति इस्तखार उर्फ चांदबाबू, परबान पत्नी गुणभरन, रिहाना पत्नी इसरार, इसरार पुत्र मो. शमी, एजाज पुत्र मो. शमी, बेबी पत्नी एजाज, पुत्रिया पुत्र मो. शमी और साहिबा नूजी गुणभरन ने मिलकर उसकी बहन रुबी को मारा-पीटा और गला दबाकर हत्या कर दी।

पड़ेगा। इस मौके पर सांसद तुनज पुनिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविन्द कुमार सिंह गोप, गांधीवादी राजनाथ शर्मा, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता अमीर हैदर, धीरेन्द्र वर्मा, शिव शंकर शुक्ला, पूर्व विधायक शिव करन सिंह, पूर्व सांसद ए.पी. गौतम आदि गणमान्य अतिथियों ने स्व. श्यामलाल बाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावधनी व्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविन्द सिंह गोप ने कहा कि श्याम

लाल बाजपेयी बेबाकी, ईमानदारी और संघर्ष के पर्याय थे। उन्होंने छत्र राजनीति से राजनीति में पदार्पण किया। वह कभी विचारधारा से अलग नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अन्याय और शोषण को प्रतिकार किया। पूर्व सांसद ए.पी. गौतम ने कहा कि शिवशंकर शुक्ला द्वारा आयोजित यह आयोजन श्यामलाल बाजपेयी को जीवंतता प्रदान करता है। वह सामाजिक एकता के पुरोध थे। वह हमेशा सामाजिक न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सीएक्यूएम को लगाई फटकार कहा, कर्तव्य निभाने में रहे असफल

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कर्तव्य निभाने में असफल रहने पर फटकार लगाई है। वहीं सीएक्यूएम की दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने की मांग को ठुकरा दिया है।



बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने का समय मांगा था। जिस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि आयोग अपना कर्तव्य निभाने में

असफल रहा है। वहीं अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न

मुख्य कारणों पर रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आयोग को दो हफ्ते में एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाने और बड़े प्रदूषण के मुख्य कारणों पर एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या आप प्रदूषण के कारणों की पहचान कर पाए हैं? इन सभी दिनों में बहुत सारा मटेरियल पब्लिक डोमेन में आ रहा है, एक्सपर्ट्स आर्टिकल लिख रहे हैं, लोगों की राय है, वे हमें मेल पर भेजते रहते हैं।

टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश

पीठ ने आगे कहा कि भारी वाहन इसमें (वायु प्रदूषण) बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसलिए पहला सवाल यह है कि हम इससे कैसे निपटें। 2 जनवरी को मीटिंग करके और हमें यह बताना कि हम दो महीने बाद आएंगे, यह हमें मंजूर नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अपनी इयूटी निभाने में नाकाम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने और विभिन्न हितधारक के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर भी विचार करने का निर्देश दिया है।

हितधारक के रुख से प्रभावित हुए विरोधियों की बैठक बुलाने और बड़े प्रदूषण के मुख्य कारणों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

'देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है आरएसएस'



जन एक्सप्रेस/एजेंसी। बंगलूरु

कानूतिक के मंत्री प्रियांक खरो ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। प्रियांक खरो ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दायर कानूनी मामले संगठन के बारे में उनकी ओर से उदात्त गए सवालों की प्रतिक्रिया हैं। प्रियांक खरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार का लेख साझा किया, जिसमें बताया गया था कि एक आरएसएस सदस्य की ओर से दायर मानहानि की शिकायत के मामले में एक विशेष अदालत ने उन्हें और राज्य

'कठपुतलियों से दर्ज कराया रहे मामले', बोले प्रियांक खरो
उन्होंने कहा, 'कुछ चुनिंदा लोगों का समूह अपने कठपुतलियों का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ मामले दर्ज कराया रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम आरएसएस पर जायज सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।' उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, 'मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस अपने स्वयंसेवकों के लिए गए दान से चलता है। हालांकि, इस दावे के संबंध में कई जायज सवाल उठते हैं: ये स्वयंसेवक कौन हैं और इनकी पहचान कैसे होती है? दिए गए दान का पैमाना और स्वरूप क्या है? ये दान किन तरीकों या माध्यमों से प्राप्त होते हैं? उन्होंने आगे सवाल किया, 'अगर आरएसएस पारदर्शी तरीके से काम करता है, तो दान सही संगठन को उसकी अपनी पंजीकृत पहचान के तहत क्यों नहीं दिया जाता? पंजीकृत संस्था न होते हुए भी आरएसएस अपनी वित्तीय और संगठनात्मक संरचना को कैसे बनाए रखता है? पूर्णकालिक प्रचारकों को वेतन कौन देता है और संगठन के नियमित परिचालन खर्चों को कौन पूरा करता है? बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों, अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों का वित्तपोषण कैसे होता है?'

आरएसएस पर खड़े किए कई सवाल

कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा, 'जब स्वयंसेवक स्थानीय कार्यालयों से वदी या अन्य सामग्री खरीदते हैं, तो इन निधियों का हिसाब कहाँ रखा जाता है? स्थानीय कार्यालयों और अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव का खर्च कौन उठाता है? ये प्रश्न पारदर्शिता और जवाबदेही के मूलभूत मुद्दे को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी व्यापक उपस्थिति और प्रभाव के बावजूद आरएसएस अभी भी पंजीकृत क्यों नहीं है? जब भारत में प्रत्येक धार्मिक या धर्मार्थ संस्था के लिए वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य है, तो आरएसएस के लिए ऐसी जवाबदेही व्यवस्था का अभाव किस आधार पर उचित है?'

के साथी मंत्री दिनेश गुंडु राव को नोटिस जारी किया है। अपने पोस्ट में खरो ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन अपने स्वयंसेवकों के चर्चे से चलता है। इस दावे पर सवाल उठते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा।

आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर सदन में हंगामा



जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होते ही हंगामेदार हो गया। सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही की शुरुआत आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के साथ हुई। भाजपा के विधायक अजय महावर ने सदन में इस मुद्दे को उठते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। महावर ने मांग की कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। सदन में बढ़ता हंगामा और गरमगरमी को देखते हुए,

'केजरीवाल और 'आप' गैंग ने झूठ बोले, उन्हें शर्म आनी चाहिए'

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली भाजपा विधायकों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा, 'केजरीवाल और आप गैंग ने झूठ बोला, उन्होंने दावा किया कि हमने कुत्तों को लेकर कोई ऑर्डर पास किया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज हमने विधानसभा में मांग की कि वे इसके लिए माफी मांगें। हम मांग करते हैं कि वे दिल्ली से, अध्यापकों से और पूरे देश से माफी मांगें।'

शिक्षा मंत्री का केजरी को पत्र

इस मुद्दे पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को पत्र लिखा है। जिसमें आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रामक और तथ्यहीन बयान देने का आरोप लगाते हुए इसे अफवाह फैलाने वाला बताया है। आशीष सूद ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की

जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल को लिखे एक लेटर में मंत्री ने कहा, 'आपने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि टीचरों को आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़ी इयूटी दी जा रही है। ये दावे न सिर्फ गलत हैं, बल्कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने जैसा भी है।'

थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का रास्ता साफ

हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा ने कहा, यह श्रद्धालुओं की जीत, डीएमके पर सनातन विरोधी होने का आरोप

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

मुद्दे। तमिलनाडु के मुद्दे स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपधूतन में दीपम जलाने को लेकर चल रहे विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए श्रद्धालुओं को राहत दी है। अदालत के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे आस्था की जीत बताते हुए डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पीयूष का डीएमके पर हमला

दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु सरकार लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके नेताओं ने न सिर्फ सनातन धर्म का उपहास



किया, बल्कि उस पर बार-बार हमला भी किया है।

उदयनिधि स्टालिन के बयान का किया जिक्र

पीयूष गोयल ने उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के सितंबर 2023 के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। गोयल ने कहा कि इसके कुछ ही महीनों बाद भगवान कार्तिकेय और भगवान मुरुगन से जुड़े पवित्र तिरुपरनकुंद्रम पर्वत पर दीप जलाने पर रोक लगाई गई, जो चिंताजनक है।

अन्नाद्रमुक ने डीएमके सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, राज्यपाल से की न्यायिक जांच की मांग

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। चेन्नई

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडम (एआइएडीएमके) के महासचिव एडुप्राडी पलानीस्वामी ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि 2021 से अब तक हूए कथित भ्रष्टाचार की एक विस्तृत सूची उन्होंने राज्यपाल को सौंपी और मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग की।



राज्यपाल से की न्यायिक जांच की मांग

उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाए। नेता ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य जनता के सामने सच्चाई आण। उनके अनुसार, डीएमके सरकार ने जनता के हित में कार्य करने के बजाय केवल सत्ता का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन व्यापक घोटालों की गहराई से जांच होना अनिवार्य है।

रही है। विपक्ष के नेता ने दावा किया कि उनके पास इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, जिन्हें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्होंने पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हुए वित्तीय नुकसान का विवरण देते हुए कहा कि सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। साथ ही, उन्होंने पीटीआर की उस कथित ऑडियो क्लिप का भी हवाला दिया जिसमें भारी भरकम रकम के लेन-देन का जिक्र था। उन्होंने दावा किया कि राज्य की शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

भाजपा आईटी सेल के ऐप से एसआईआर करा रहा चुनाव आयोग: ममता बनर्जी बोलीं, यह अवैध, असाविधानिक और अलोकतांत्रिक, योग्य मतदाताओं को किया जा रहा परेशान

'एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग हर तरह के गलत और मनमाने तरीके अपना रहा है'

एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेते समय सतर्क रहें और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हों

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। कोलकाता

गंगानगर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है।

गंगासागर दोरे के बाद पत्रकारों से बातचीत

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दक्षिण 24

परगना जिले के सागर द्वीप में गंगासागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग हर तरह के गलत और मनमाने तरीके अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य मतदाताओं को मृत घोषित किया जा रहा है, जबकि बुजुर्ग, बीमार और असहाय लोगों को सुनवाई के लिए जबर्न बूलाया जा रहा है।

भाजपा आईटी सेल के ऐप के इस्तेमाल का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए भाजपा के आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल एप का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इसे अवैध, असाविधानिक और



अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि ऐसी प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो को यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पार्टी के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम

जनता से सतर्क रहने की अपील

ममता बनर्जी ने जनता से अपील की कि एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेते समय सतर्क रहें और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि लोगों को उनका समर्थन करने की नहीं, बल्कि उन नागरिकों का साथ देने की जरूरत है जो इस प्रक्रिया से परेशान हैं।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान

मुख्यमंत्री ने सोमवार को भी कहा था कि वह राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डर, उपीड़न और प्रशासनिक मनमानी के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, मौतें हो रही हैं और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है।

लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

रमेश कुमार जुनेजा ने काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन का पदभार संभाला

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली



प्रवर्तित कंपनियों अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें लेदर (जेसी ग्रुप), लेदर एक्सपोर्ट्स, केमिकल्स (इंडोटेन केमिकल्स) तथा रियल एस्टेट (जुनेजा इंफ्रास्ट्रक्चर) प्रमुख हैं। जुनेजा का लेदर उद्योग से जुड़ाव चार दशकों से अधिक का है। जेसी ग्रुप के संस्थापक के रूप में उन्होंने 1980 के दशक में रिटेलर्स के साथ साझेदारी कर उन्हें फिनइंड लेदर के

नामांकित टैरन के रूप में आपूर्ति कर उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने तीव्र प्रगति की और फिनइंड लेदर निर्माण के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम बनी। समय के साथ समूह ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए विश्वभर के रिटेलर्स के लिए उत्पाद, एक्सपोर्ट्स एवं जूते निर्माण की दिशा में विस्तार किया। जुनेजा पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से CLE के बोर्ड सदस्य हैं और वर्ष 2014 से इंस्टैंट रीजन के रीजनल चेयरमैन के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वे अप्रैल 2024 से CLE के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने विशेष कौशल एवं अनुभव के माध्यम से संपादन और उद्योग को दिशा दी, जिसके परिणामस्वरूप लेदर गुड्स एवं सैफ्टी वियर के निर्यात में एंथ्रोमेट्रिक उपलब्धियाँ हासिल हुईं। इसके अतिरिक्त, जुनेजा इंडो-इंटीग्रेटिव चैंबर

ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भी हैं और रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड तथा लेदर जैसे क्षेत्रों में भारत-इटली सहयोग के तहत महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। वे कलकत्ता लेदर कॉम्लेक्स टैन्स एसोसिएशन के संस्थापक समिति सदस्य रहे हैं तथा एक दशक से अधिक समय तक इसके अध्यक्ष भी रहे। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर टैरनी मालिकों को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। उनके प्रयासों से पश्चिम बंगाल सरकार ने कॉमन एफ्टरपुट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी ढाँचों के उन्नयन हेतु 800 करोड़ का निवेश किया। CLE को विश्ववास है कि श्री रमेश कुमार जुनेजा के नेतृत्व में भारतीय लेदर उद्योग को नई ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी और निर्यात के क्षेत्र में और अधिक मजबूती आणी।

केरल की जेल में 85 वर्षीय पॉक्सो मामले के आरोपी की दूसरे कैदी ने पिटाई की, मामला दर्ज

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। केरल

केरल के जेल में एक अन्य कैदी ने पॉक्सो मामले में आरोपी की पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि अलापुझा के जिला जेल में एक 85 वर्षीय आरोपी को कथित तौर पर एक अन्य कैदी ने पीट दिया। आरोपी ने दावा किया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह दो बेटियों का पिता है। अधिकारी ने बताया कि किसी तरह, चोरी और मारपीट के कई मामलों का सामना कर रहे दूसरे कैदी को पता चला कि 85 वर्षीय व्यक्ति यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामले में आरोपी है और उसने उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने कहा, 'हमने जेल के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।' उन्होंने आगे बताया कि पॉक्सो मामले के आरोपी के चेहरे पर चोट आई।

ठाणे की जेल में बंद कैदी ने मचाया बवाल पुलिसवालों से की मारपीट, सीसीटीवी तोड़े

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। ठाणे



महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ठाणे जिले की एक सब-जेल में बंद कैदी ने जेल में तैनात पुलिसवालों और पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान कैदी ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए तुरंत रिहाई की मांग की और जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। उसने यह भी दावा किया कि उस पर कानूनी कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि वह पहले भी ऐसे मामलों का सामना कर चुका है। फैयाज इस्लाम शेख के रूप में हुई कैदी की पहचान

लिया और उन्हें फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। इस दौरान उसने तीन लाइट बल्ब भी तोड़ दिया। पुलिसवालों को देख लेने की धमकी

इस दौरान जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे शांत करने और प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका कॉन्टैक्ट पकड़ लिया और उसे धक्का दिया। उसने वहां मौजूद स्टाफ से कहा कि इंडियन पीनल कोड की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला) के तहत पहले लगे आरोप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

कैदी के खिलाफ केस दर्ज

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं, 132, 352, 351(2) (आपराधिक धमकी) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है।